● वर्ष-3

● अंक-240

रायपुर, शुक्रवार
17 मई 2024

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

samacharpacheesa@gmail.com

पेज-6›› युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा....

चुनावी रण में आरक्षण को लेकर दांव-पेंच

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण को लेकर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जैसे-जैसे यह चुनाव उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है, आरक्षण पर विपक्ष जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष साफ तौर पर दावा करता दिखाई दे रहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो वह आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी और साथ ही साथ लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हालांकि, बीजेपी इन तमाम आरोपों से इनकार कर रही है। इसके अलावा भाजपा यह भी कह रही है कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता में आते हैं तो वह ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण लेकर मुसलमान को दे देगी। फिलहाल देखें आरक्षण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने-अपने दावे हैं और लोगों के समक्ष इसको पेश करने की भी कोशिश कर रहे हैं।

आप नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में आने पर भाजपा संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। उन्होंने कहा, बीजेपी के लोग हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहे हैं। सत्ता में आने के बाद वे संविधान बदल देंगे और आरक्षण खत्म कर देंगे।%% केजरीवाल ने अपना दावा दोहराया कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव का भी दावा है कि भाजपा भारत और विश्व स्तर पर सबसे खतरनाक परिवार है। वे और एक अन्य खतरनाक परिवार आरक्षण ख़त्म करना चाहते थे, अब अन्यथा दावा करके वोट मांग रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है कि हम आरक्षण के लिए और संविधान को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आप संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। भाजपा पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि आपको आरक्षण के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस संविधान में बदलाव कर पूरे देश में यह नियम लागू करना चाहती है लेकिन पिछड़े वर्ग को धोखा देने वाली सपा इस पर चुप है... ये लोग मोदी के खिलाफ वोट जिहाद की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं कांग्रेस को धर्म के नाम पर दलितों, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए मिलने वाले आरक्षण को मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि यदि हमारा लक्ष्य आरक्षण हटाना होता, तो हमारे पास 10 वर्षों के लिए बहुमत होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। जहां तक मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है तो मेरी अब भी यही राय है कि इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, यह संविधान की योजना नहीं है, संविधान इससे सहमत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी।

देश में यह पहला मौका नहीं है जब आरक्षण को लेकर जबरदस्त राजनीति हो रही है। विपक्षी खेमा हमेशा से भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाता रहा है और इसका फायदा भी उन्हें मिला है। चुंकि भाजपा इस चुनाव में पूरी तरीके से हिंदुत्व के नाव पर सवार होकर मैदान में है। विपक्ष को पता है कि हिंदुत्व की राजनीति का काट जाति हो सकता है और यही कारण है कि विपक्ष की ओर से बार-बार आरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है। साथ ही साथ इसमें जातीय जनगणना का भी चाशनी लगा दिया जाता है। लेकिन इस बार भाजपा के पास से भी अपना पक्ष मजबूती से रखने का पूरा मौका है।

4 जून के बाद इंडि गठबंधन बिखरेगा खटाखट-मोदी

प्रतापगढ़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के शब्दों का स्पष्ट मजाक उड़ाते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को इंडिया ब्लॉक पर हमला करते हुए कहा कि विपक्षी मोर्चा 4 जून के बाद खटाखट खटाखट बिखर जाएगा, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए, उन्होंने राहुल गांधी के राजस्थान में दिए गए भाषण से शब्द उधार लिए, जहां सांसद ने कहा था कांग्रेस सरकार देश के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक खाते में 1 लाख रुपये (एक साल में) ट्रांसफर करेगी... अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो हर साल 1 लाख रुपये (8,500 रुपये प्रति माह) खटाखट खटाखट आता रहेगा और एक झटका से हम हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। नाम लिए बिना, प्रधान मंत्री ने कहा कि राहुल और कांग्रेस रायबरेली से हार जाएंगे, जो प्रमुख रूप से भगवाकृत यूपी में पार्टी के आखिरी कुछ गढ़ों में से एक है। गांधी को उनकी मां की जगह लेने और उनके निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए चुना गया है। राहुल पर वार करते हुए मोदी ने कहा कि अमेठी से गए हैं, रायबरेली से भी जाएंगे। 4 जून के बाद इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा खटाखट खटाखट; ये शहजादे गरमी की छुट्टियाँ में विदेश की यात्रा पर निकल जायेंगे। मुझे सूचना मिली है कि टिकट भी बुक कर लिया गया है। मोदी ने कहा कि इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की... इसलिए ये कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा... देश का विकास खटाखट होगा। ये सोचते हैं कि भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएगा और पूछो तो कहते हैं- खटाखट...खटाखट। ये कहते हैं कि भारत की गरीबी हम दूर कर देंगे- खटाखट...खटाखट। लेकिन अब इनको मालूम होना चाहिए कि रायबरेली की जनता भी खटाखट... खटाखट भेजेगी घर। अमेठी से गए और अब ये रायबरेली से भी जाएंगे। देश चलाना, सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है।

राहुल के ठकाठक वाले बयान पर मोदी का पलटवार

प्रधान मंत्री ने कहा कि शहजादे चाहे लखनऊ वाले हों या दिल्ली वाले... गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे- खटाखट... खटाखट। और मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सेवा के लिए दिन-रात एक करके काम करूंगा। मेरा पल-पल आपके नाम, मेरे शरीर का कण-कण आपके नाम। उन्होंने कहा कि सपा-कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास, गिल्ली-डंडे के खेल की तरह है। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को न मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए ये कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा - खटाखट-खटाखट। ये कहते हैं कि भारत की गरीबी हम दूर कर देंगे- खटाखट...खटाखट। लेकिन अब इनको मालूम होना चाहिए कि रायबरेली की जनता भी इनको खटाखट... खटाखट भेजेगी घर।

हम राष्ट्रीय स्तर पर 'इंडि' का हिस्सा- ममता

तमलुक। सत्ता में आने पर विपक्षी गठबंधन 'इंडि' को बाहर से समर्थन देने की घोषणा के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी गठजोड़ का हिस्सा है और आगे भी रहेगी। तमलुक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और कांग्रेस के साथ गठबंधन में नहीं है। बनर्जी ने कहा, "कुछ लोगों ने कल के मेरे बयान को गलत समझा है...अखिल भारतीय स्तर पर, मैं पूरी तरह से इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूं। इंडिया गठबंधन का मैंने सुझाव दिया था। हम राष्ट्रीय स्तर पर साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे।" बनर्जी ने आरोप लगाया कि 'इंडिया' गठबंधन में शामिल माकपा और कांग्रेस दोनों की पश्चिम बंगाल इकाइयां ने हाथ मिला लिया है और राज्य में भाजपा की मदद कर रही हैं। उन्होंने रैली में कहा, "बंगाल में माकपा और कांग्रेस पर भरोसा नहीं करें। वे हमारे साथ नहीं हैं, वे यहां भाजपा के साथ हैं...।"

सुको ने 17 विदेशी घुसपैठियों को वापस भेजने का आदेश दिया

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 17 विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार से कहा कि तत्काल 17 विदेशी नागरिकों को वापस भेज जाए, जिन्हें असम के एक डिटेंशन कैंप में रखा गया है। केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस एएस ओका ने टिप्पणी की कि जो संसाधन इन लोगों पर खर्च हो रहे हैं, वे भारत के लोगों को मिलने चाहिए। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच ने कहा कि इन 17 लोगों के पास भारत में कोई केस दर्ज नहीं है। ऐसे में उन्हें वापस भेजने में कोई अड़चन नहीं है। अदालत ने कहा, रिपोर्ट से पता चलता है कि असम में डिटेंशन सेंटर है, जिसे ट्रांजिट कैंप भी कहा जाता है। डिटेंशन सेंटर में घोषित तौर पर 17 विदेशी मौजूद हैं, जिनमें से 4 तो दो साल से यहीं हैं। हमारा मानना है कि केंद्र सरकार को तत्काल इन्हें वापस भेजने के लिए कदम उठाने चाहिए। इन लोगों के खिलाफ किसी अपराध के तहत मुकदमा भी दर्ज नहीं है। सबसे पहले उन 4 लोगों को वापस भेजना चाहिए, जो 2 साल से डिटेंशन सेंटर में हैं। अदालत ने कहा कि इस मामले में क्या ऐक्शन लिया गया, इसकी रिपोर्ट दो महीने के अंदर सौंपी जाए। अब इस केस की अगली सुनवाई कोर्ट ने 26 जुलाई को करने का फैसला लिया है। यह फैसला असम के डिटेंशन सेंटर्स की स्थिति को लेकर दिया गया।

नक्सलियों पर की जा रही कार्रवाई पर कांग्रेस का सवाल उठाना दुःखद- साय

रायपुर। नक्सलियों पर की जा रही कार्रवाई को लेकर कांग्रेस द्वारा सवाल खड़े किये जाने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दु:खद बताया है। श्री साय ने कहा कि कांग्रेस को इन सब विषयों को राजनीती से ऊपर उठकर देखना चाहिए।

पुलिस ग्राउंड हेलीपेड पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली बार जब 29 नक्सली मारे गए, तब कांग्रेस और विपक्ष के लोग इस घटना को नकली बता रहे थे, जबकि स्वयं नक्सलियों ने 29 लोगों का लिस्ट जारी किया। ये बहुत ही दु:ख की बात है। अब इन लोगों को क्या कहें, ये लोग तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करने वाले लोग हैं। उनसे मेरा यह आग्रह है कि इन सब विषयों को राजनीती से ऊपर उठकर देखें।

मुठभेड़ को कांग्रेस द्वारा फर्जी कहे जाने पर इसका खंडन करते हुए सीएम साय ने कहा कि लगातार हमारे जवानों को सफलता मिल रही है। उन्होंने पुनर्वास नीति पर कहा कि हमारी पुनर्वास नीति के कारण नक्सली आत्मसर्पण भी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस नीति में और नया बेहतर हो सकता है, साथ ही नई पुनर्वास नीति लाने पर विचार किया जा रहा है।

गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल मोर्चे पर विष्णु सरकार को मिल रही सफलता के लिए उसकी जमकर तारीफ की है। जिस पर कांग्रेस प्रश्न उठा रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे गृह मंत्री के आभारी हैं कि उन्होंने हमारी सरकार पर विश्वास जताया है। यह सब डबल इंजन सरकार की वजह से संभव हुआ है कि मात्र 3-4 महीनों में 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग पौने चार सौ नक्सली आत्मसमर्पण किये हैं और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। ये हमारी सुरक्षाबलों के लिए बड़ी सफलता है। श्री साय बोले कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस विषय पर बहुत ही गंभीर है और जल्द ही छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का समापन चाहते हैं।

प्रमुख समाचार

पहले चार चरणों में 66.95 प्रतिशत हुई वोटिंग

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने मौजूदा लोकसभा चुनाव के पहले चार चरणों में 66.95% के भारी मतदान की घोषणा की। लगभग 45.10 करोड़ मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के साथ, चुनाव पैनल ने शेष चरणों में निरंतर भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उत्साहजनक मतदान के जवाब में, चुनाव आयोग ने मतदाताओं से आगामी चरणों में अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखने का आग्रह किया। मतदाताओं को सूचित करने, प्रेरित करने और सुविधा प्रदान करने के प्रयास तेज हो गए हैं, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को उन्नत उपाय लागू करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में साझेदारी और सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने विभिन्न संस्थानों, प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों की उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया के लिए सराहना व्यक्त की, जो सक्रिय रूप से मतदाता भागीदारी को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 379 सीटों पर शुरुआती चरण में मतदान हो चुका है।

मेरे साथ बहुत बुरा हुआ...स्वाति मालीवाल ने तोड़ी चुप्पी

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने कथित हमले पर आप सांसद स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज किया। उन्होंने केजरीवाल के स्टाफ सदस्य द्वारा मारपीट की लिखित शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस की एक टीम गुरुवार को आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल के आवास पर गई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी द्वारा उन पर किए गए कथित हमले के संबंध में उनका बयान दर्ज किया। आप सांसद ने बिभव कुमार द्वारा किए गए हमले पर एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि उचित कार्रवाई की जाएगी। तीन दिन बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए स्वाति मालीवाल ने एक्स पर लिखा कि मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्यवाही होगी। पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहे हैं। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका धन्यवाद करती हूँ। जिन लोगों ने करेक्टर असैनिनेशन करने की कोशिश की, ये बोला की दूसरी पार्टी के इशारे पर कर रही है, भगवान उन्हें भी खुश रखे।

पूर्व रॉ और एनआईए प्रमुख को मिली जेड+ की सुरक्षा

नई दिल्ली। केंद्र ने पूर्व एनआईए प्रमुख दिनकर गुप्ता को जेड+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह सुरक्षा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) द्वारा प्रदान की जाएगी और मार्च 2024 से पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली में लागू होगी। पंजाब कैडर के 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी दिनकर गुप्ता ने एनआईए के रूप में कार्य किया। जून 2022 से 31 मार्च 2024 तक प्रमुख। उन्होंने पहले पंजाब में पुलिस महानिदेशक (खुफिया) के रूप में कार्य किया है। खालिस्तानी आतंकी समूहों से बढ़ते खतरों के बीच सरकार की ओर से दिनकर गुप्ता की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार को प्रमुख पदों पर काम कर चुके अधिकारियों पर खतरे बढ़ने का संकेत देने वाली खुफिया जानकारी मिली है। खासतौर पर कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से चरमपंथी समूह और अधिक आक्रामक हो गए हैं। पंजाब पुलिस में दिनकर गुप्ता का कार्यकाल उल्लेखनीय उपलब्धियों से भरा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने पंजाब में संगठित अपराध से निपटने के लिए पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई।

दिलीप घोष के पोलिंग एजेंट का मिला शव

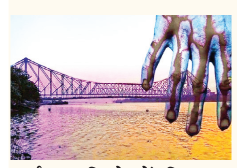

नई दिल्ली। 15 मई की रात से लापता एक भाजपा कार्यकर्ता का शव गुरुवार को पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्दवान जिले में मिला। इसके बाद से एक नया विवाद पैदा हो गया और स्थानीय भाजपा नेताओं ने दावा किया कि उसकी हत्या टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की है। हालांकि, सत्तारूढ़ टीएमसी ने इस आरोप से इनकार किया है। अभिजीत रॉय मंतेश्वर के जमना क्षेत्र में भाजपा बूथ अध्यक्ष और बूथ संख्या 168 के पोलिंग एजेंट थे। मंतेश्वर बर्दवान-दुर्गापुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है जहां दिलीप घोष भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। पुलिस के अनुसार, ग्रामीणों को गुरुवार सुबह एक फार्महाउस में रॉय का शव मिलने के बाद मंतेश्वर पुलिस स्टेशन की एक टीम ने उसे बरामद किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। रॉय की मौत की खबर फैलने के तुरंत बाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मंतेश्वर पुलिस स्टेशन के सामने इकट्ठा होने लगे और हत्या का मामला दर्ज करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए परिसर का घेराव किया।

एस्ट्राजेनेका के कोविड वैक्सीन को लेकर रिसर्च में नया खुलासा

नई दिल्ली। ब्रिटिश फॉर्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका की तरफ से बिक्री में गिरावट और बाजार में पर्याप्त विकल्पों की उपलब्धता का हवाला देते हुए दुनिया भर से अपनी कोविड 19 वैक्सीन को वापस मंगवा लिया है। लेकिन अब एस्ट्राजेनेका के कोविड वैक्सीन को लेकर रिसर्च में नया खुलासा हुआ है। शोधकर्ताओं ने पाया कि भारत में कोविशील्ड ब्रांड नाम के तहत बेची जाने वाली एस्ट्राजेनेका वैक्सीन-प्रेरित इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और थ्रोम्बोसिस (वीआईटीटी) नामक एक दुर्लभ रक्त के थक्के जमने की बीमारी से जुड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी और अन्य अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ताओं ने अपने ताजे रिसर्छ में ये दावा किया है। वीआईटीटी 2021 में कोविड-19 महामारी के दौरान उभरकर सामने आई, विशेष रूप से ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के उपयोग के बाद से ही। इसे एडेनोवायरस पर आधारित बताया गया। वैज्ञानिकों ने पाया कि वीआईटीटी एक हानिकारक रक्त ऑटोएंटीबॉडी के कारण होता है जो प्लेटलेट फैक्टर 4 (पीएफ4) नामक प्रोटीन को टारगेट करता है। 2023 में अलग-अलग शोध से घातक विकार का पता चला, जो सामान्य सर्दी जैसे प्राकृतिक एडेनोवायरस संक्रमण से जुड़ा है। ऑटोएंटीबॉडी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा उत्पादित एक प्रकार का एंटीबॉडी है जो गलती से शरीर के स्वयं के ऊतकों को निशाना बनाती है।

दीदी, वाम और श्रीराम- बंगाल का चुनाव, सबका अपना-अपना दांव

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को नौ राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के मतदाताओं ने 96 सांसदों को चुनने के लिए मतदान किया। 19 अप्रैल को आम चुनाव शुरू होने के बाद से लोकसभा की 543-379 सीटों में से लगभग 70% पर मतदान हो चुका है। भारत के सभी दक्षिण और उत्तर-पूर्व में मतदान हो चुका है। शेष सीटें उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे प्रमुख राज्यों से आती हैं।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए)

भाजपा और तृणमूल के बीच कांटे की टक्कर में गंगा के मैदानी इलाकों के साथ ही जंगलमहल इलाका, उत्तर बंगाल और दक्षिण बंगाल का मतुआ बहुल इलाका अहम भूमिका निभाएगा। मतुआ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ही भाजपा ने चुनाव से ठीक पहले नागरिकता (संशोधन) कानून लागू करने का फैसला किया है। राज्य में करीब एक करोड़ आबादी वाला मतुआ समुदाय 5 सीटों (बशीरहाट, बनगांव, कृष्णनगर, जलपाईगुड़ी और अलीपुर) पर असर डालता है क्योंकि, यहां इनकी आबादी 25-30त्न तक है। सीएए के विरोधियों का कहना है कि यह भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक है क्योंकि यह आस्था को नागरिकता से जोड़ता है और मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवश्यक मूल देशों के कानून और दस्तावेजों को नियंत्रित करने वाले नियमों में स्पष्टता की कमी के बारे में भी मतुआ लोगों में चिंताएं हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से सीएए के तहत आवेदन नहीं करने को कहा है क्योंकि इससे उनके निवास को खतरा होगा।

नेताओं पर ईडी-सीबीआई की कार्रवाई

पिछले एक दशक से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार के प्रति एंटी इनकमबेंसी और टीएमसी नेतृत्व की मनमानी पर गुस्से के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा भी गूंज रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी में रिश्वतखोरी (स्थानीय रूप से कट मनी कहा जाता है) का आरोप लगाया गया है। ममता बनर्जी ने 2019 में टीएमसी कार्यकर्ताओं से कट मनी वापस करने को भी कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बार-बार टीएमसी नेताओं के खिलाफ संघीय जांच का आदेश दिया है, यहां तक कि न्यायमूर्ति अभिजीत बंदोपाध्याय के भाजपा में शामिल होने और चुनाव लड़ने के कदम ने सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आरोपों को कमजोर कर दिया है। टीएमसी ने बंदोपाध्याय पर भाजपा में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से इस्तीफा देने से पहले राजनीति से प्रेरित फैसले देने का आरोप लगाया है।

अल्पसंख्यक वोट का ध्रुवीकरण

टीएमसी अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक को बचाने की कवायद में जुटी है। इसी वजह से उसने कांग्रेस और सीपीएम के साथ तालमेल की बजाय अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मोटे अनुमान के मुताबिक, राज्य में इस तबके की आबादी 30त्न से ज्यादा है। पिछली बार अल्पसंख्यक वोटों के विभाजन के कारण भाजपा को उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिलों की एक-एक सीट पर जीत मिली थी। टीएमसी का लक्ष्य अबकी इस बिखराव को रोकना है। हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी को शिक्षक भर्ती घोटाले और राशन घोटाले में तमाम मंत्रियों नेताओं के जेल में रहने का खामियाजा उठाना पड़ सकता है। वहीं राम मंदिर निर्माण, मुस्लिम तुष्टिकरण और पाकिस्तान जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर नहीं है, भले ही बनर्जी के विरोधी उन पर मुसलमानों के लिए काम करने का आरोप लगाते हैं। कुछ ध्रुवीकरण है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इसका टीएमसी विरोधी वोटों में कितना असर होगा। 2022 में भी इसी तरह की कहानी को आगे बढ़ाया गया लेकिन टीएमसी ने विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की।

लेफ्ट-कांग्रेस गठबंधन

गठबंधन भले ही ज्यादा सीटें न जीत पाए लेकिन कुछ सीटों पर नतीजों पर असर डाल सकता है। माना जाता है कि 2019 में लेफ्ट वोट बीजेपी को ट्रांसफर हो गए। इस बार ऐसी स्थिति बनने की संभावना नहीं है. राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि अगर गठबंधन टीएमसी के सत्ता विरोधी वोटों में कटौती करता है, तो टीएमसी को फायदा होगा। कैडर को छोड़कर बाकी लोग गठबंधन को बड़ी संख्या में वोट नहीं दे सकते. अगर गठबंधन मुस्लिम वोटों में सेंध लगाता है तो यह बनर्जी के लिए बुरी खबर है। वाम दलों ने एक दर्जन से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अगले तीन चरणों में अधिकांश मुस्लिम बहुल सीटों पर मतदान होने जा रहा है।

आगे निकलने की बीजेपी की कोशिश

अबकी बार चार सौ पार के नारे के साथ मैदान में उतरी भाजपा ने राज्य की 42 में से कम से कम 25-30 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। टीएमसी ने भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में 26 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। गंगा के मैदानी इलाके अपनी 16 सीटों के कारण काफी अहम हैं। यहां संगठन की मजबूती के बल पर टीएमसी भाजपा से आगे नजर आती है। उत्तर बंगाल में भी टीएमसी ने अपने पैरों तले की खिसकती जमीन बचाने के लिए आदिवासियों के लिए कई विकास योजनाएं शुरू की है। आदिवासी-मुस्लिम संयोजन भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है, जिसने 2019 में बंगाल में 18 सीटें जीतीं। भाजपा ने बिरसा मुंडा और आउटरीच कार्यक्रमों जैसे अपने प्रतीकों का जश्न मनाकर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की है।

अंतर्राज्यीय चोर गिरोह से मिली विदेशी मुद्राएं

दुर्ग। भिलाई के प्रमुख कॉलोनियों में चोरी और नबकजनी की वारदातों में शामिल गिरोह के तीन सदस्यों को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से स्वर्ण आभूषण सहित आठ लाख रुपये नगदी बरामद की है। पुलिस ने गिरोह के पास से विदेशी मुद्रा भी जप्त की है।

उल्लेखनीय हैं कि भिलाई के शांति नगर, नेहरु नगर, साकेत कॉलोनी, स्मृति नगर के सुने मकानों को निशाना बनाते हुए गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। चोरी की इन वारदातों को लेकर पुलिस आरोपियों की अपने स्तर पर सरगर्मी के साथ तलाश कर रही थी, लेकिन उनके हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत उनके हाथ नहीं लगा। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए संदिग्ध मोटर सायकल सवार चार व्यक्तियों में से एक ही पहचान कर पुलिस हरियाणा पहुंची। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के शाहबाद डेहा कालोनी से आरोपी सुखविन्दर सिंग को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरु की। पहले तो सुखविंदर ने इन वारदातों में अपना हाथ होने से इंकार किया लेकिन जब पुलिस ने सख्ती बरती तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बताया कि वह भिलाई निवासी सूरतजीत सिंह के बुलाने पर यहां आया था और यहां पर वारदातों को अंजाम देने के बाद हिस्सा बटवारे के बाद वह वापस हरियाणा अपने गांव लौट गया। सुखविंदर की निशानदेही पर सूरजीत सिंह को पुरानीबस्ती कोहका से गिरफ्तार किया और चोरी का माल खरीदने के आरोप में बलांगिर ओडिशा के नरेश साहू को गिरफ्तार किया।

पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने स्वर्ण

आभूषणों सहित नगद राशि और विदेशी मुद्रा में दीनार, रियाल, इण्डोनेशियन, मलेशियन करेन्सी, यूरो यूरो के मुद्रा को जप्त किया है। पुलिस ने स्वर्ण आभूषणों सहित जप्त की गई नगदी को मिलाकर 8 लाख रुपये बमराद किए है।

एक ही रात तीन सूने मकानों में चोरी

खैरागढ़। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में एक ही रात में तीन सूनें मकानों का ताला तोड़कर जेवरात समेत नगदी रकम पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वारदात की पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में चोर हॉफ चड्डे पहने हुए ताला तोड़ते हुए दिख रहे हैं। यह मामला डोंगरगढ़ शहर के आउटर में बस रहे सलंग रोड का है, जहां अधिकतर नौकरीपेशा लोग रहते हैं।

भारतीय वायुसेना नागपुर में सार्जेन्ट के पद पर कार्यरत हेमंत साहू अपने डोंगरगढ़ स्थित घर में ताला लगाकर 28 अप्रैल को नागपुर चले गए थे। इस दौरान 14 मई की रात अज्ञात चोरों ने सूने मकान का ताला तोड़कर घर के अंदर घुसे और जेवर समेत नगदी रकम को पार कर दिया। चोरों ने सोने व चांदी के जेवर व नगदी रकम मिलाकर करीब 58 हजार रुपए की चोरी की है। घटना की जानकारी दूसरे दिन सुबह जवान के ससुर ने फोन पर दी तब वे नागपुर से डोंगरगढ़ पहुंचे और थानें में एफआईआर दर्ज कराया।

हेमंत के पड़ोसी शिवराज सिंह ठाकुर व नंदकुमार देवांगन के मकानों को भी चड्डा गैंग के सदस्यों ने अपना शिकार बनाया है। दोनों मकानों से चोरों ने करीब एक लाख रुपए के जेवर व नगदी रकम पार कर दिए। तीनों चोरी एक ही रात में हुई है। बता दें कि सलंग रोड अभी आउटर पर है। यहां पर घनी आबादी न होने से चोरों ने लम्बे समय से बंद मकानों को अपना शिकार बनाया है। चोरों की पूरी हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरें में कैद हो गई है। फुटेज को पुलिस को सौंप दिया गया है।

वारदात को तीन लोगों ने मिलकर अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज में तीनों की हरकत दिख रही है, जो पेंचिस व पेचकस लेकर सूने मकान का ताला तोड़ते दिख रहे। तीनों हॉफ चड्डा पहने हुए हैं इसलिए पुलिस इन्हें चड्डा गैंग का सदस्य बता रही है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है और जांच के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा, लेकिन एक ही दिन में रहवासी इलाके में तीन-तीन मकानों के ताले तोड़कर लाखों की चोरी होने से पुलिस विभाग की सतर्कता पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

कबीरधाम में डायरिया का प्रकोप दो गांवों में मिले करीब 80 मरीज

कबीरधाम। सहसपुर लोहारा ब्लॉक अंतर्गत दो गांव में डायरिया फैल गई है। इन दोनों गांव में करीब 80 मरीज मिले हैं। जानकारी अनुसार कोयलारी गांव में बीते 6 मई से शुरू हुआ डायरिया का प्रकोप जारी है। इस गांव के 56 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। वहीं, इसी गांव के एक बुजुर्ग की बुधवार रात जिला अस्पताल कवर्धा में मौत हो गई। हालांकि, अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बुजुर्ग को टीबी की बीमारी थी। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

इसी प्रकार दैहानडीह गांव में दो दिन पहले शादी कार्यक्रम में भोजन खाने से 31 लोगों की तबीयत खराब हुई। इन लोगों में से एक को जिला अस्पताल भेजा गया है। ग्राम कोयलारी में डायरिया फैलने का प्रमुख कारण गांव के एक कुएं का पानी है, जो दूषित हो गया था। इसी पानी को पीने से डायरिया फैली है। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने मामले को तत्काल संज्ञान मे लेते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में भेजकर बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद अब गांव की स्थिति में सुधार हुआ है।

कलेक्टर महोबे ने एसडीएम, एसडीओ पीएचई और सीएमएचओ की संयुक्त टीम गठित कर जांच करने के निर्देश दिए थे। संयुक्त टीम द्वारा ग्राम कोयलारी मे पहुंचकर वाटर सैंपल लेकर जांच की गई। जांच के बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने बताया कि 10 वाटर सैंपल लिये गए, जिनमें से दो सैंपल जांच में पेयजल की गुणवत्ता खराब पायी गई है, जहां साइन बोर्ड लगाकर उपयोग के लिए मना

किया गया है।

दोबारा कुछ जल स्त्रोतों से सैंपल लिए गए हैं। सभी पेयजल स्त्रोतों में ब्लीचिंग घोल डाला गया है तथा क्लोरीनेशन भी किया गया है। ग्रामीणों को कुएं का पानी उपयोग ना करने एवं बोर, नल का पानी उबाल कर स्वच्छता के साथ पीने की सलाह जिला प्रशासन द्वारा दी गई। अब तक कुल मरीजों की संख्या 57 है। मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट और सुधार है। गांव मे डोर-टू-डोर सर्वे का कार्य जारी है। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने गुरुवार सुबह सहसपुर लोहारा ब्लॉक के ग्राम कोयलारी और दैहानडीह ग्राम का दौरा किया। स्थाई स्वस्थ्य कैंप का अवलोकन किया। दोनों ग्रामों के स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही गांव में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई जा रही है, जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी व्यक्ति को उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो गांव के प्राथमिक विद्यालय में हेल्थ विभाग द्वारा शिविर लगाई गई है। शिविर का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा पानी को उबालकर ठंडा कर पिएं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 100 बच्चों ने पास की 10वीं-12वीं की परीक्षा

■ **14 लाख का ईनामी नक्सली भी उत्तीर्ण**

कबीरधाम। कबीरधाम पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के 200 से अधिक बच्चों का छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के कक्षा 10वीं व 12वीं की परीक्षा के लिए फॉर्म भरवाया था। बुधवार को छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने परीक्षा परिणाम जारी किए। ओपन स्कूल परीक्षा में 14 लाख रुपये का इनामी नक्सली समेत 100 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं।

कबीरधाम एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव ने बताया कि वर्ष 2023-24 में 200 से अधिक बच्चों को कक्षा 10वीं व 12वीं का ओपन परीक्षा का फॉर्म भरावाया गया था। अधिक दूरी होने के कारण स्कूल व कोचिंग सेंटर तक पहुंचने में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए वनांचल के शिक्षित युवाओं के माध्यम से ही नक्सल प्रभावित गांवों के विद्यार्थियों को कोचिंग के माध्यम से पढ़ाई कराई गई।

परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों में 14 लाख रुपये का इनामी नक्सली दिवाकर भी शामिल है। दिवाकर ने वर्ष 2021 में सरेंडर किया था। सरेंडर के बाद पढ़ाई शुरू की और आज पास हो गया है। 200 बच्चों में से 105 उत्तीर्ण हो गए हैं। वहीं, अन्य विद्यार्थी, जो कुछ विषय में फेल हुए हैं, वे आने वाले समय में संबंधित विषय की परीक्षा में शामिल होंगे। कबीरधाम जिले में ओपन स्कूल का परीक्षा केंद्र

ब्लॉक मुख्यालय में है। ऐसे में केंद्र तक परीक्षा दिलाने के लिए वाहन की व्यवस्था की गई थी। सभी विद्यार्थी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के चिल्फी, तरेगांव जंगल, रेंगाखार जंगल, झलमला जंगल व बोड़ला ब्लॉक के सुदूर वनांचल गांव के हैं।

एडिशनल एसपी विकास कुमार सिंह ने बताया कि पिछले वर्ष में भी 100 अधिक विद्यार्थी ने ओपन स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद कुछ शासकीय सेवा, कुछ स्वरोजगार व कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं। जिला पुलिस का उद्देश्य है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बच्चे भी शिक्षा से जुड़ें। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं। इस कारण लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है व पुलिस के प्रति नजरिया बदला है।

एसडीओ ने सॉ मिल में दी दबिश, प्रतिबंधित लकड़ी पाए जाने पर आरा मशीन सील

बालोद। बालोद जिले में चल रहे प्रतिबंधित लकड़ियों के कारोबार को लेकर उप वन मंडल अधिकारी डिंपी बैस ने धनकर आरा मिल में दबिश दी। धनकर आरा मिल रजोली में अर्जुन लट्ठा का अवैध चिरान करते पाया गया। आरा मिल परिसर में रखे अर्जुन प्रजाति के लट्ठा व चिरान का नापजोख कर एक बैंड सॉ, एक ट्रॉली और एक मोटर जब्त किया। एसडीओ डिंपी बैंस की इस कार्रवाई से जिले भर के आरा मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।

एसडीओ डिंपी बैस ने बताया कि कहुआ अर्जुन की लकड़ी प्रतिबंधित प्रजाति है। राजस्व क्षेत्र में निजी व्यक्ति द्वारा कटाई के लिए कलेक्टर/एसडीएम से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुमति के बाद ही इसे काट सकते हैं। साथ ही इसके परिवहन के लिए रेंजर द्वारा टीपी जारी किया जाता है। इनमें से किसी भी प्रक्रिया को अगर अपनाया नहीं जाता तो अवैध कटाई राजस्व क्षेत्र में राजस्व टीम द्वारा भू-राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई की जाती है।

उन्होंने बताया कि आरा मिल में कहुआ की लकड़ी का किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं था। इसलिए छत्तीसगढ़ काष्ठ चिरान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर मिल को सील करते हुए लकड़ी एवं चिरान जब्त किया गया। डिंपी वैष्णव बताया कि बालोद जिले में सभी जगह पर आकस्मिक निरीक्षण कर जांच पड़ताल की जा रही है। जहां पर भी लापरवाही और नियम के विपरीत कार्य किए जा रहे हैं, वहां पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आवश्यक दस्तावेज का होना आवश्यक है।

आपको बता दें कि वन विभाग द्वारा लगातार दौरा किया जा रहा है। तेंदुपत्ता संग्रहण के साथ-साथ प्रतिबंधित लकड़ियों की कटाई एवं परिवहन को लेकर भी निगरानी की जा रही है। इसी के तहत यह कार्रवाई की गई है। सभी मिलों का बारी-बारी से निरीक्षण किया जा रहा है।

हत्या की वरादात में शामिल 1 लाख के ईनामी 2 नक्सली गिरफ्तार

सुकमा। जिले में चलाये ला रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत नक्सलियों की उपस्थिति की आसूचना पर थाना चिंतागुफा से टी सैमसन राजू, डिप्टी कमाण्डेन्ट 2 वाहिनी सीआरपीएफ एवं निरीक्षक अनुराग सोनवानी, थाना प्रभारी चिंतागुफा के हमराह 02 वाहिनी सीआरपीएफ एवं जिला बल की संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन/आरसीएसओ ड्यूटी हेतु ग्राम दुलेड़ व आस-पास क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे।

अभियान के दौरान ग्राम दुलेड़ के पास से 2 नक्सलियों मड़कम गंगा पिता मड़कम लखमा (मिलिशिया कमाण्डर दुलेड़ आरपीसी अन्तर्गत ईनामी 1 लाख) निवासी ग्राम दुलेड़ थाना चिंतागुफा एवं ओयाम भीमा पिता स्व. हुंगा (चिन्नाबेड़केल आरपीसी अध्यक्ष) निवासी चिन्नाबोड़केल थाना चिंतलनार को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दोनो नक्सलियों को थाना लाकर नक्सल रिकार्ड की जा करने पर दोनों नक्सलियों द्वारा थाना चिंतागुफा क्षेत्रार्न्गत 1 सितंबर 2023 को मिनपा जाने वाले मार्ग में 01 ग्रामीण का अपहरण कर हत्या करने की वारदात में अन्य नक्सलियों के साथ शामिल रहना पाया गया। उक्त वरादात के संबंध में थाना चिंतागुफा में अपराध क्रमांक 08/2023 धारा 147, 148, 149, 302 भादवि. 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पूर्व से दर्ज है। उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही उपरांत आज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

आईपीएल में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाले रैकेट का भंडाफोड़

गौरेला पेंड्रा मरवाही। आईपीएल मैच में मोबाइल फोन से ऑनलाइन सट्टा खिलाने के रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी जो पहले भी आईपीएल मैच में सट्टे के मामले में गिरफ्तार हो चुका था वो फरार हो गया है। पुलिस ने आरोपियों के बैंक खाते सीट करवा दिए हैं और उनके पास मोबाइल में 30 से अधिक लिंक मिले जिनके जरिए क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने का काम किया जाता था। जानकारी के मुताबिक, पेंड्रा पुलिस को मुखबीरों से सूचना मिली कि पेंड्रा इलाके में आईपीएल मैचों में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा खिलाने का कारोबार कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस ने अपने मुखीबिरों को एक्टिव किया और साइबर सेल और पेंड्रा पुलिस की टीम ने दुबटिया छपराटोला में जाकर दबिश दी। जहां पर तीन व्यक्ति मोबाइल फोन से सट्टा खिलाते पाए गए। बाजार पारा का रहने वाला प्रकाश केवट और लोहतरैया पारा के रहने वाले हर्ष जायसवाल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं एक अन्य आरोपी मौके से फरार हो गया है।

कटघोरा के जंगल में तेंदुए का शिकार, कई अंग मिले गायब

कोरबा। कटघोरा वन मंडल के चैतमा रेंज में तेंदुए के शिकार का मामला सामने आया है। बुधवार को राहा जंगल में तेंदुए का शव मिला। जांच में पाया कि तेंदुए का नाखून, दांत समेत कई अंग गायब हैं। तेंदुए के शिकार की सूचना से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर प्रभात मिश्रा, डीएफओ कुमार निशांत, एसडीओ चंद्रकांत टिकरिया के साथ मौके पर पहुंचे। रायपुर से डॉग स्क्वायड की टीम भी बुला ली ली गई है। चैतमा रेंज के कक्ष क्रमांक पी 25 बीट राहा में तेंदुआ का शव मिलने की सूचना पर वन विभाग में तेंदुए के अंग गायब मिलने के बाद रायपुर में बड़े अधिकारियों को सूचना दी गई। यह स्पष्ट हो गया कि तेंदुए का शिकार किया गया है। तीन पशु चिकित्सकों की टीम ने तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम किया। डीएफओ कुमार निशांत का कहना है जहर देकर तेंदुए को मारा गया है। आसपास आरोपियों की तलाश की जा रही है। जांच के लिए अलग-अलग टीम लगाई है। रायपुर से डॉग स्क्वायड को भी बुला लिया गया है।

फर्जी दस्तावेज पेश कर लोन लेने वाले पटवारी गिरफ्तार

जांजगीर-चांपा। जमीन का फर्जी दस्तावेज तैयार कर एचडीएफसी की राजिम शाखा से 22 लाख रुपये का लोन लेने वाले पटवारी दयाराम साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने कुछ अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार देवरानी ग्राम के नम्मूराम पटेल ने जिले के बिर्रा थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी कि सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के पवनी के रहने वाले परमानंद कर्ष और उसके साथियों ने ग्राम सिलादेही के तत्कालीन पटवारी दयाराम साहू से मिलीभगत कर एक जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी की है और उसी जमीन के आधार पर 22 लाख रुपये का ऋण एचडीएफसी की राजिम शाखा से उठाया है। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि पटवारी साहू ने 2.5 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से 12 एकड़ दर्ज कर दिया और उस पर डिजिटल हस्ताक्षर किया था, जिसके आधार पर कर्ष को बैंक से ऋण मिल गया। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 34 और 120 के तहत अपराध दर्ज कर लिया था।

कुए में गिरा तेंदुआ, वन विभाग के कर्मचारियों ने निकाला बाहर

कांकेर। जिले के ग्राम सारवंडी में एक ग्रामीण के घर बाड़ी के कुएं में एक वन्य प्राणी तेंदुआ गिर गया, गुरूवार सुबह जब कुएं से पानी निकालने पंहुचे तो देख कि कुए में एक तेंदुआ पानी में तैर रहा है, इसकी सूचना ग्राम पंचायत के माध्यम से वन विभाग को दिया गया। सूचना पर इलाके में तैनात वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचकर स्थानिय ग्रामीणों की मदद से तेंदुए को कुएं से रस्सी और बांस से बने झूले के माध्यम से बाहर निकालने के बाद तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। विदित हो कि कांकेर वन मंडल के ईलाके में वन्य प्राणी तेंदुआ और भालू अक्सर रिहईसी इलााके में भोजन, पानी की तलाश में पंहुच जाते हैं। वैसे भी इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रहा है, मई के महीने में कांकेर में 40 डिग्री तापमान में इंसानों के साथ-साथ जंगली जानवरों को भी बेचैन कर रखा है, लिहाजा जंगली जानवर भोजन, पानी की तलाश गांव की तरफ रुख कर रिहायसी इलाकों में पहुंच रहे है, जिसे लेकर लोगों में भी भय व्याप्त है।

गुलाब की खेती से प्रदेश के किसान कर रहे मोटी कमाई

महासमुंद। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में सिर्फ धान की ही खेती नहीं बल्कि फूलों की भी खेती हो रही है। छत्तीसगढ़ में ऐसे युवाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो देश विदेश में आईटी सहित अन्य क्षेत्रों में काम करने के बाद अब अपने गांव लौटकर खेती को अपना करियर बना रहे हैं। ये युवा परंपरागत तरीके से खेती करने के बजाय आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं। गुलाब के फूल की खेती करने में लागत बहुत कम आती है और वहीं अन्य फसलों की अपेक्षा आय भी अधिक होती है। यहीं नहीं फूलों की खेती करने में खेत की उर्वरक क्षमता में भी कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि फसल की पैदावार के लिए कोई भी कीटनाशक दवा का उपयोग नहीं किया जाता है। महासमुंद किसान अमर चंद्राकर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर गांव लौटने पर गुलाब की खेती के प्रयोग को आधुनिक तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस काम में उन्हें सरकार की बागवानी योजना के तहत अनुदान और तकनीक का सहयोग मिला।

अरपा नदी के उद्‌गम स्थल की भूमि का होगा अधिग्रहण

■ **रिवाइवल कमेटी के बैठक में हुआ फैसला**

बिलासपुर। अरपा रिवाइवल कमेटी की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि अरपा के उद्गम स्थल का एक बार फिर अगले सप्ताह निरीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही भिलाई की आईआईटी टीम पूरे क्षेत्र का सर्वे करते हुए रिपोर्ट तैयार करेगी। अरपा के उद्गम स्थल को संरक्षित करने के लिए 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करनी होगी। जहां एक जल कुंड और स्टाप डेम का निर्माण होगा। यह पूरी रिपोर्ट 26 जून को हाईकोर्ट में पेश की जाएगी।

जिला कार्यालय के सभाकक्ष में अरपा रिवाइवल कमेटी की बैठक आयोजित की गई। अरपा के पुनर्जीवन के संबंध में हाई कोर्ट में दाखिल पीआईएल के बाद कार्यों में आई प्रगति की समीक्षा की गई। गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) कलेक्टर लीना मण्डावी, निगम आयुक्त अमित कुमार और भिलाई आईआईटी के निदेशक सहित याचिकाकर्ता अरविन्द कुमार शुक्ला, न्यायमित्र आशुतोष कछवाहा, इकोलॉजिस्ट डॉ। नीरज तिवारी, अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता एवं जिला कलेक्टर द्वारा गठित उप

समिति के सदस्य शामिल हुए।

बैठक में मुख्य चर्चा आईआईटी भिलाई द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण तथा अरपा नदी में आईआईटी द्वारा किये जा सकने वाले सर्वे कार्य को प्रारंभ करने और विश्लेषित करने पर रहा। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बैठक में प्रस्ताव दिया कि आईआईटी के रिसर्च स्कॉलरों की अरपा नदी के भौतिक सर्वे से पूर्व मुख्य परिस्थितियों से उन्हें अवगत कराया जाये और नदी की विभिन्न समस्याओं तथा विभागीय कार्यों, जिसे पहले ही कार्य-योजना में शामिल कर लिया गया है। उन कार्यों के विश्लेषण और मूल्यांकन संबंधी सुझाव प्रदान किये जाएं। इकोलॉजिस्ट डॉ। नीरज तिवारी की ओर से वानिकी और कलेक्टर की ओर से स्थापित उप समितियों में से प्रदत्त सभी जानकारियों को एकीकृत कर आईआईटी के भौतिक सर्वेक्षण जो कि लाईडर सर्वे होगा, जिससे विस्तृत परियोजना प्राक्कलन तैयार किया जाए और मूलतः नदी के उद्गम स्थल का भूमि अधिग्रहण कर यथाशीघ्र प्रशासकीय रूपरेखा तैयार किया जाये।

अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता ने आने वाले 26 जून को न्यायालय में प्रस्तुत करने वाले दस्तावेज तैयार करने का सुझाव दिया। जीपीएम कलेक्टर लीना मण्डावी ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्राथमिकता से किये जाने की जानकारी दी गई। इस क्रम में समिति अगले सप्ताह अरपा उद्गम स्थल का दौरा करने का निर्णय भी लिया गया।

कर्नाटक राज्य बंधक बनाये गये 13 मजदूर वापस लौटे, कलेक्टर ने की मुलाकात

जगदलपुर। कर्नाटक में बंधक बनाये गये बस्तर से मजदूरों का संपर्क जिला प्रशासन से होने पर प्रशासन ने कर्नाटक राज्य के संबंधित जिला के प्रशासन और पुलिस विभाग से समन्वय कर श्रम विभाग के माध्यम से कर्नाटक के प्रशासन की मदद से वापस लाए गए कोलेंग क्षेत्र के 13 मजदूरों से कलेक्टर विजय दयाराम ने मुलाकात कर उन्हाने मजदूरों से कहा कि राज्य शासन द्वारा जनकल्याण की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा और पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर दिया जा रहा है, इसका लाभ लें। यदि रोजगार की तलाश में पलायन करके अन्य राज्य जाने की स्थिति में भी ग्राम पंचायत में स्थित पलायन पंजी में जानकारी दिया जाना चाहिए। कर्नाटक राज्य से वापस लाए गए 13 मजदूरों ने बताया कि अधिक मजदूरी की लालसा में सुकमा होते कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा पहुंचे थे, जहां पर 05 लोग टेंट के कार्य और 08 लोग सुपारी

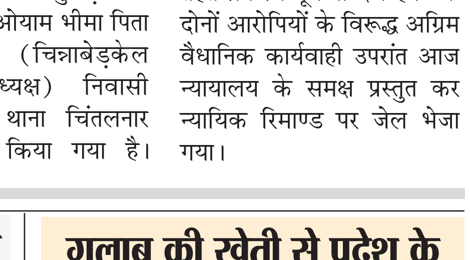

के बगीचे में काम किया करते थे। लेकिन उन्हें तीन-चार महिने का मेहनताना नहीं दिया गया था और अपने घर वापस आने के लिए रोका जा रहा था। मजदूरों को कर्नाटक राज्य की शासकीय दर 14 हजार 100 रूपए (मासिक दर) नियोजक से मजदूरों को भुगतान करवाया गया। 13 श्रमिकों को 05 लाख 93 हजार 500 रूपए ठेकेदार से भुगतान की कार्यवाही करवाई की गई। मजदूरों ने कलेक्टर से मिलकर मजदूरी भुगतान और घर वापस लाने के लिए आभार व्यक्त किए।

स्वयं के विकास के साथ समाज में भागीदारी ही वास्तविक सफलता : बोरा

प्रमुख सचिव ने सड्डू स्थित प्रयास विद्यालय और निर्माणाधीन एकलव्य आवासीय भवन का किया निरीक्षण

रायपुर। आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज सवेरे सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यालय में जेईई, आईआईटी सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से रूबरू हुए। श्री बोरा ने कहा कि हमारे यहां इतिहास है कि एकलव्य बिना गुरू के भी लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। हमें यहां शिक्षा को प्राथमिकता में रखकर लक्ष्य तक पहुंचना है। उन्होंने कहा कि तरक्की तो कोई भी कर लेता है, लेकिन स्वयं का विकास करना ही सफलता नहीं होता है। स्वयं के विकास के साथ समाज में भागीदारी ही वास्तविक सफलता है। उन्होंने कहा कि माता-पिता ने जिस उद्देश्य से आपको यहां भेजे हैं, उनके सपने को पूरा करना है। साथ ही ऐसे समाज जो हमारे पीछे छूट गए हैं, उनको भी आगे बढ़ाने की सोच रखना होगा।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने प्रयास आवासीय विद्यालय का निरीक्षण के दौरान अधिकारियो से कहा कि शासन प्रशासन की मंशा अनुरूप आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा तथा कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए फाइव स्टार होटलों की तरह सुविधाएं उपलब्ध हो। अतः होटलों की तरह इन वर्ग के बच्चों के लिए सुविधाएं विकसित कु जाय। उन्होंने प्रयास विद्यालय हॉस्टल के किचन का निरीक्षण कर बच्चों के लिए भोजन व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवोदय विद्यालय की तर्ज पर प्रयास विद्यालय को भी विकसित किया जाए। श्री बोरा ने प्रयास विद्यालय स्थित भौतिक और रसायन विज्ञान प्रयोगशाला सहित लाईब्रेरी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को थ्योरी के साथ-साथ प्रेक्टिकल भी कराने के निर्देश दिए। श्री बोरा ने लाईब्रेरी में आवश्यक सभी किताबे, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने डायनिंग हॉल का निरीक्षण करते हुए डायनिंग हॉल को होटलों की तरह साफ-सफाई के साथ ही सुसज्जित करने को कहा। उन्होंने आवासीय विद्यालय परिसर को सी.सी.टीव्ही. कैमरा से लैस करने के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि सड्डू स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय में नवमीं व दसवीं के छात्रों के लिए 400 सीट और ग्यारवीं-बारहवीं के बच्चों के लिए 400 सीट उपलब्ध है। प्रयास विद्यालय में कमजोर वर्ग के बच्चे पढ़ाई करते है।

श्री सोनमणि बोरा ने इस दौरान सड्डू में बन रहे व्यावसायिक शिक्षा, शोध और इंजीनियरिंग सहित प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 22.05 करोड़ रूपए की लागत से बन रहे 750 सीटर आवासीय एकलव्य भवन का भी निरीक्षण किया। इनमें बालिकओं के लिए 250 सीट और बालकों के लिए 500 सीटर की अलग-अलग दो ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। श्री बोरा ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधयों से कहा कि गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में भवन का निर्माण किया जाना सुनिश्चित हो। श्री बोरा ने धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते1 हुए निर्माण कार्य मे तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नियमित रूप से निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच भी किया जाय। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण के पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आगामी समय के लिए क्या सुविधाएं दी जा सकती है अथवा क्या-क्या आवश्यकता पड़ सकती है। बोरा भ्रमण के दौरान निर्माण एजेंसी से कहा कि कॉलोनाइजर की तरह एक कमरा मॉडल के रूप तैयार कर लिया जाय और उसके अवलोकन और सुधार के बाद बाकी निर्माण किया जाय, ताकि भविष्य के हिसाब से सुविधाओं को ध्यान में रखा जा सके।

इस अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के ईई श्री त्रिदीप चक्रवर्ती, सहायक अभियंता श्री प्रकाश अनंत, प्रयास विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती मंजूला तिवारी, प्राचार्य श्रीमती प्रमिला शुक्ला, मेट्रिक्स संस्था के प्रतिनिधि श्री राजेश बोढ़े सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

सिक्किम वासियों को मुख्यमंत्री साय ने दी स्थापना दिवस की शुभकामनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सिक्किम वासियों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि अनूठी लोककला, संस्कृति और ईश्वर द्वारा प्रदत्त अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सिक्किम राज्य के स्थापना दिवस पर सिक्किम वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विविध क्षेत्रों में यह राज्य निरंतर प्रगति करे और यहां के रहवासियों का जीवन सुगम हो इसकी कामना करता हूं।

राज्य पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए 9 जून तक करें ऑनलाइन आवेदन

रायपुर । छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है। राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून तक लिए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यापम के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा के कार्यक्रम अनुसार ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 13 मई और अंतिम तिथि 9 जून है। त्रुटि सुधार की सुविधा 10 जून से 12 जून तक रहेगी। परीक्षा 21 जुलाई 2024 को संभावित है। पात्रता परीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं ली जाएगी। पात्रता परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाईट vyapam.cgstate.gov.in और https://vyapamaar.cgstate.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

चेंबर के संविधान संशोधन पर विवाद के बीच पूरनलाल अग्रवाल ने किया स्वागत

रायपुर। चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष पूरनलाल अग्रवाल ने चेंबर के संविधान संशोधन को विधिसम्मत बताते हुए इसका स्वागत किया है। वहीं चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज टीम कैट के मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह देव ने संविधान संशोधन को असंवैधानिक बताए जाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में आयोजित आमसभा में इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया था। विक्रम सिंह देव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि संविधान संशोधन के लिए आहुत बैठक में सभी लोग मौजूद थे। इसके अलावा 25 हजार व्यापारियों को हमने डाक के जरिए प्रेस रिलीज भेजा है। यही नहीं चेंबर के वरिष्ठ सदस्य पूरनलाल अग्रवाल ने इस बिल का स्वागत किया है। इस बिल संशोधन को स्वागत किया है। बता दें कि चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संविधान संशोधन के खिलाफ पूर्व चेंबर अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी ने रजिस्ट्रार फर्म सोसायटी के साथ वाणिज्य मंत्री लखन देवांगन से शिकायत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 27 अप्रैल को चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष द्वारा चेंबर भवन में विशेष आमसभा बुलाकर संविधान में संशोधन किए गए हैं। इस संविधान संशोधन का न तो प्रकाशन किया गया, और न ही सूचना पत्र जारी किया गया था।

रायपुर की सड़कों में लगे टायर फाड़ने वाले स्पीड ब्रेकर अवैध

रायपुर। राजधानी रायपुर की सड़कों पर रैग साइड से आ रही गाड़ियों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के टायर फाड़ने वाले टायर किलर लगाए है। लेकिन अब आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्ट में इसे लगाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। टायर किलर कौन से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लगाया गया है इसके संबंध में आरटीआई कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई का जवाब देते हुए कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक एवं जनसूचना अधिकारी, यातायात रायपुर ने ये बताया है कि 'टायर फाड़ने वाले स्पीड ब्रेकर लगाए जाने के संबंध में मोटर व्हीकल एक्ट में कोई प्रावधान नहीं हैं'। राजधानी रायपुर के एक्सप्रेस-वे समेत राजधानी के कई जगहों पर लगे टायर किलर की वजह से कई लोगों की गाड़ियों के टायर फटे। हालांकि अब ये टायर किलर कई जगहों से आधे गायब भी हो गए है और कई जगहों पर ब्रेकर में लगने वाली स्प्रिंग भी खराब हो गई है। अब सवाल ये है कि आरटीआई से खुलासे के बाद जब ये टायर किलर अवैध हो गए है तो इन्हें रायपुर ट्रैफिक पुलिस निकालती है या ये अवैध ब्रेकर ऐसे ही लगे रहेंगे?

इंद्रप्रस्थ नाले के पास 2.55 एकड़ की अवैध प्लाटिंग पर निगम ने लगाई रोक

रायपुर। निगम मुख्यालय एवं जोन 8 नगर निवेश विभाग की टीम ने माधव राव सप्रे वार्ड के तहत रायपुरा में इन्द्रप्रस्थ नाले के पास अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लगभग 2.55 एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर रोक लगा दी है। निगम के अमले ने थ्रीडी एवं श्रमिकों की सहायता से यह कार्यवाही की। यहां बनाए गए मुरूम रोड को थ्रीडी से काटकर सभी प्लाटों की अवैध नींव को तोड़ा। जोन 8 नगर निवेश विभाग के माध्यम से रायपुर तहसीलदार को पत्र लिखकर निजी भूमि के भूमि स्वामियों की जानकारी शीघ्र उपलब्ध करवाने कहा गया है। जानकारी आते ही राज्य शासन के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के विरूद्ध पुलिस में नामजद एफआईआर दर्ज करवायी जायेगी।

मुख्यमंत्री साय को उद्योग मंत्री ने लिखा पत्र

सीएसआर मद को राज्य सरकार के माध्यम से खर्च करने का किया आग्रह

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव को उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने सीएसआर मद के व्यय को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र के माध्यम से सीएसआर मद का व्यय और निर्माण कार्य को राज्य सरकार द्वारा संपादित करने और केंद्र सरकार से समन्वय बनाने के लिए सीएम साय से आग्रह किया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में अभी सीएसआर राशि के व्यय पर राज्य शासन का अधिकार नहीं है। पिछले विधानसभा सत्र में कई विधायकों ने सीएसआर राशि के व्यय पर सवाल भी लगाए थे।

उद्योग मंत्री ने मुख्यमंत्री साय को पत्र में लिखा- पिछले विधानसभा सत्र के दौरान कई विधायकों के माध्यम से उद्योगों के लाभ से सृजित होने वाली सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) मद से होने वाले कार्यों की जानकारी शासन से मांगी गई थी, छत्तीसगढ शासन स्तर पर सीएसआर मद और निर्माण में व्यय करने संबधी किसी भी प्रकार के नियम व अधिकार शामिल नहीं होने के कारण उद्योग विभाग द्वारा न कोई कार्य संपादित किया जा रहा है, और न ही सीएसआर से होने वाले व्यय की समीक्षा व सही जानकारी प्राप्त हो पा रही है। उन्होंने सीएम साय का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह किया है कि सीएसआर का व्यय शासन स्तर पर किया जाए, तो उद्योगों से प्रभावित लोगों की मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि हो पाएगी, साथ ही पर्यावरण को हो रहे नुकसान की भरपाई की जा सकती है। श्रम एवं उद्योग मंत्री ने सीएसआर मद से होने वाले व्यय व निर्माण कार्य राज्य शासन से संपादित करने और इस संबंध में स्पष्ट नीति नियम बनाने, भारत शासन से आवश्यक समन्वय करने का आग्रह किया है। प्रदेश में संचालित राष्ट्रीय स्तर की सार्वजनिक और निजी उपक्रम, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट समेत सभी उद्योग सीएसआर मद के तहत सालाना 1 हजार करोड़ खर्च करते हैं। मंत्री श्री देवांगन का प्रयास है की राज्य शासन के माध्यम से ये राशि खर्च हो ताकि उद्योगों से प्रभावित लोगों के साथ-साथ ज्यादा जरूरतों पर जैसे- स्वास्थ, शिक्षा, कुपोषण, सिंचाई,आधारभूत संरचना पर सीएसआर राशि खर्च हो।

भाजपा के दिग्गज नेता राजेश मूणत ने पुरी में संभाला मोर्चा, कहा-

ओड़िशा में भाजपा की बनेगी सरकार : मूणत

पुरी। छत्तीसगढ़ में चुनाव खत्म होते ही भाजपा के दिग्गज नेताओं ने ओडिशा में पूरे दमखम से प्रचार शुरु कर दिया है। इस समय ओडिशा में लोकसभा चुनाव के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। चुनाव में जनता का विश्वास जीतने के लिए भाजपा ने पूर्व मंत्री और विधायक राजेश मूणत को पुरी लोकसभा सीट के लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी दी सौंपी है।

बता दें, भाजपा ने पुरी लोकसभा सीट से लोकप्रिय नेता संबित पात्रा और पुरी के विधानसभा सीट से विधायक जयंत कुमार सारंगी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं विधायक राजेश मूणत ने ओडिशा में भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा है कि, ओड़िशा में डबल इंजन की सरकार बनेगी।

विधायक मूणत ने कहा कि, पुरी भगवान जगन्नाथ की भूमि हैं। इस पवित्र भूमि में रहने वाले लोग रामभक्तों के साथ हैं। उन्होंने कहा- पुरी की जनता ने तय कर लिया है, कि जो अयोध्या में भगवान राम को लाये हैं, उन्हें ही देश और राज्य की बागडोर सौंपनी हैं।

उन्होंने आगे कहा- मैं पुरी विधानसभा सीट के कोने- कोने तक जा रहा हूं, यह पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, कि आमजनों के मन में हमारी प्रत्याशी जयंत कुमार सारंगी और संबित पात्रा के प्रति बेहद स्नेह है। लोगो ने तय कर लिया है, कि वह भाजपा के पक्ष में मतदान करके ओड़िशा में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से ओड़िशा में भाजपा की सरकार बनेगी।

मूणत ने कहा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में ओडिशा की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। ओडिशा की एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बनी हैं, जिससे ओड़िशा के साथ ही आदिवासियों का सम्मान बढ़ा है, जबकि बीजद के 25 साल के शासन में मुख्यमंत्री पटनायक ने ओड़िशा को 50 साल पीछे धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि जनता ने अब नवीन बाबू को अलविदा कहने का मन बना लिया है। पुरी में भाजपा रिकॉर्डतोड़ मतों से जीतेगी। ओडिशा का अगला मुख्यमंत्री भाजपा नेता और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मूणत ने कहा, कि पुरी में भाजपा के विपक्षी दलों ने अभी से हार स्वीकार कर ली है। बीजेडी के खेमे में निराशा का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी सुचारिता ने चुनाव लड़ने से किया इनकार करके भाजपा की जीत पहले ही तय कर दी है। राजेश मूणत ने बताया कि ओड़िशा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बेहद मजबूत है। आगामी 20 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी 20 मई (सोमवार) को पुरी में रोड शो करेंगे, इसको लेकर आमजनों में बेहद उत्साह देखा जा रहा है।

छत्तीसगढ़ भाजपा महिला मोर्चा चुनावी मैदान में, बिहार और ओडिशा रवाना

रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा मिशन 400 पार को सफल बनाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों में भाजपा की जीत के लिए चुनावी मैदान में कूद चुकी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ महिला मोर्चा की तीन टोली बनाई गई है। पहली टोली हरियाणा, दूसरी टोली बिहार और तीसरी टोली ओडिशा के लिए रवाना हुई है। इस टीम का नेतृत्व मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत कर रही हैं।

इस दौरान शालिनी राजपूत ने कहा कि हम अपनी टीमों को अच्छी तरह से भाजपा के रीती नीति और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मिशन को पूरा करने के लिए अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर बिहार एवं हरियाणा के घर-घर जाकर महिलाओं को देश के प्रति सनातन के प्रति भारतीय जनता के पार्टी के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमारी टीम जिस प्रकार से अपने कुशल नेतृत्व और कुशल कार्यशैली से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक विजय प्राप्त की ठीक उसी प्रकार से लोकसभा में भी विजय प्राप्त कर 11 में 11 सीटे जीतेगी।

उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि पूरे भारत में मोदी लहर कि सुनामी 400 पार कर एक नई क्रांति का आगाज करेगी। हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं बड़ी बहादुर और होनहार हैं, जिस प्रदेश में प्रचार करेंगी वहां पर कुछ कहने की बात नहीं रिजल्ट में दिखेगा। इतना कहते हुए शालिनी राजपूत के मार्गदर्शन में सभी महिलाओं की टोली जय श्रीराम का उद्घोष करते हुए अपनी टीम को लेकर आगे के लिए रवाना हुई।

इस दौरान महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत, प्रदेश उपाध्यक्ष मीनल चौबे, प्रदेश कोषाध्यक हेमलता शर्मा, प्रदेश सहकोषाध्यक्ष संध्या तिवारी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी आयुषी पांडे, निशा चौबे, आशा दुबे, कार्यकारिणी सदस्य मंजू सिंह, स्विटी कौशिक, मोहन कुमारी साहू, किरण साहू, वैशाली रत्नपारखी, निलिमा गोश्वामी, पार्वती प्रधानी, ममता गुप्ता, रीता मंडल आदि शामिल रहीं।

नक्सल मोर्चे पर शाह ने की प्रदेश सरकार की तारीफ

- कहा - विपक्ष दे रहा नक्सलियों को ताकत पर मुकाम तक पहुंचेगी लड़ाई

रायपुर। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के आने के बाद यहाँ नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई के दौरान मिल रही अभूतपूर्व सफलताओं के लिए सरकार की पीठ थपथपाई है। गृह मंत्री ने कहा कि ङ्क छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मात्र साढ़े चार महीने के अंदर 112 नक्सली मारे गए हैं, लगभग 375 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और 153 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 5 महीने में अभियान को जबर्दस्त सफलता मिली है। ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि डबल इंजन की सरकार नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रही है। अब प्रदेश के 3-4 जिलों में ही नक्सली बचे हैं और आगामी 2-3 वर्षों में देश नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस द्वारा इसे फेक एनकाउंटर कहे जाने पर अमित शाह ने गोस्वामी तुलसीदास के एक दोहे का उदाहरण देते हुए कहा कि जिसका बुरा समय आता है, भगवान सबसे पहले उसकी मति हर लेता है। कांग्रेस पार्टी के साथ यही हो रहा है।

गृह मंत्री अमित शाह द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उनका आभार जताया है। अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा है कि आपके इस विश्वास के लिये हम आभारी हैं माननीय गृह मंत्री जी। आपके कुशल मार्गदर्शन में हम नक्सल समस्या के स्थायी समाधान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस विषय में डबल इंजन की सरकार को बेहतरीन सफलता मिली है। निस्संदेह इस विषय पर विपक्ष द्वारा की जा रही राजनीति से नक्सलियों को ताकत मिलती है, पर बावजूद इसके हम इस लड़ाई को परिणाम तक पहुंचाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज पूरी तरह से नक्सल समेत हर तरह के आतंक को समाप्त करने के प्रति कृत संकल्पित है।

गौरतलब है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के पश्चात नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में तेजी आई है। मात्र साढ़े चार महीने की सरकार में नक्सली लगातार मारे जा रहे हैं, गिरफ्तार हो रहे हैं या सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौट रहे हैं।

सेवा और समर्पण के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अजय तिवारी का सम्मान

- अजय तिवारी की लीडरशिप में कई संस्थाओं ने सफलता के नए आयाम हासिल किए-सत्यनारायण

रायपुर। राजधानी की प्राचीनत्तम व ऐतिहासिक जैतूसाव मठ के प्रमुख रहे स्व. महंत जी की अगुवाई में पले बढ़े अजय तिवारी ने उन्ही के बताये रास्ते पर चलते हुए आज अपने जीवन के 75 वर्ष पूरे कर लिए इस मौके पर विभिन्न संस्थाओं की ओर से कचहरी चौक स्थित बाल आश्रम सभागृह में अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया था,जिसमें उनका सम्मान किया गया। उनके साथ काम कर चुके तीन पीढ़ी के सदस्य इस गरिमामय आयोजन के साक्षी बने। सभी वक्ताओं ने उनके लीडरशिप की सराहना करते हुए शतायु होने की कामना की। इस स्नेह भरे कार्यक्रम से अभिभूत अजय तिवारी ने भावुक होकर कहा कि आपके आर्शिवाद व मिले प्यार से मै आजीवन ऋणी हो गया हूं। शहर के विशिष्टजन काफी बड़ी संख्या में इस अवसर पर उपस्थित थे।

बाल आश्रम रायपुर के अध्यक्ष एवं विभिन्न शिक्षण संस्थाओं के संचालक अजय तिवारी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय विद्यालय समिति, श्रीमती पीजी डागा कन्या महाविद्यालय, राष्ट्रीय उ.मा. विद्यालय रायपुर व छतौद, बाल आश्रम रायपुर व ग्राम सेवा समिति के संयुक्त तत्वाधान में अनेक संस्थाओं ने उनका अभिनंदन कर उनके दीर्घायु होने की कामना की। शाल श्रीफल स्मृति चिन्ह से लेकर फूलमाला से स्वागत करने वालों की कतार लगी रही। इन संस्थाओं के अलावा शहर के और भी संस्थाओं और प्रबुद्धजनों ने श्री तिवारी का सम्मान किया।

पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि अपने सबसे प्रिय साथी अजय तिवारी में उन्होने सेवा और समर्पण की भावना को हर काम के प्रति देखा है.सभी को वे समान रूप से महत्व देते हैं। उनकी लीडरशिप में आज कई संस्थाओं ने सफलता के नए आयाम तय किए हैं। उन सभी की मूलभावना है जो आज इतनी बड़ी संख्या में यहां उनहे बधाई देने के लिए उपस्थित हैं। पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ला ने कहा कि उन्होने तो श्याम भैया के साथ काम करते हुए श्री तिवारी जी को देखा है और पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ आज भी वे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं.आज भले उनका 75 वां जन्मदिन मना रहे हैं लेकिन मैं तो उन्हे जवान रूप में ही देखता हूं।

इस अवसर पर देवीचंद श्रीश्रीमाल, गोकुल दास डागा, मदन लाल तालेड़ा,डॉ कमलेश अग्रवाल, राजकिशोर नत्थानी, विजय दानी, डॉ. सुरेश शुक्ला, डॉ. लक्ष्मीकांत निगम, पीआर गोलछा, गोवर्धन दास डागा, दीपक दुबे, रुपचंद श्रीश्रीमाल, शिवराज भंसाली, आरके गुप्ता, अनिल गुप्ता, ललित चौरडिया, निखिल अम्बिलकर, डॉ देवाशीष मुखर्जी, अजय दानी, शिवशंकर दानी, डॉ संगीता घई, पीडी दीवान, श्रीमती हेमलता रेड्डी, अनिल चंद्राकर, नाकेश शर्मा आदि उपस्थित रहे एवं सभी ने अजय तिवारी के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन हेतु कामना कर बधाई दी।

यात्रियों के ठहरने की परेशानी खत्म

भाठागांव बस स्टैंड में बन रहा गेस्ट हाउस

रायपुर। दूर-दराज से रायपुर आने वाले बस यात्रियों को अब कोई परेशानी नहीं होगी। रायपुर भाठागांव स्थित नया बस स्टैंड में गेस्ट हाउस तैयार हो रहा है। यात्रियों के थकावट से राहत मिल सकती है। गेस्ट हाउस जल्द से जल्द तैयार किए जा रहे हैं। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने भाठागांव बस स्टैंड में तैयार हो रहे गेस्ट हाउस का निरीक्षण किए। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। गेस्ट हाउस का संचालन जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिया गया है। इससे दूर-दराज से रायपुर आने वालों को परेशानियां नहीं होगी।

इस बस स्टैंड में बस में यात्रा करने वाले यात्रियों को ठहरने की बेहतर सुविधा मिलेगी। यात्रियों के थकावट से राहत मिल सकती है। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा और अन्य अधिकारी समेत कर्मचारी उपस्थित थे। दूसरी ओर कलेक्टर गौरव सिंह ने जयस्तंभ चैक स्थित मल्टीलेवल पार्किंग के उपरी माले में तैयार हो रहे आरंभ सेंटर का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सेंटर को जल्द से जल्द तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही रूफटॉप का उपयोग करने आवश्यक निर्देश दिए है। स्टार्टअप शुरू करने के लिए जिला प्रशासन स्थान उपलब्ध कराएगा और इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है।

भारत के लिए दो-दलीय व्यवस्था

सिद्धार्थ शंकर गौतम

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के मुखिया, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने एक अंग्रेजी समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद कई छोटे क्षेत्रीय दल या तो कांग्रेस से जुड़ जाएंगे अथवा उनका कांग्रेस में विलय हो जाएगा। हालांकि अपनी विभाजित पार्टी के कांग्रेस में विलय को लेकर उन्होंने स्पष्टता से कुछ नहीं कहा किंतु स्वयं और पार्टी की विचारधारा को गांधी-नेहरू की वैचारिक लाइन बताकर राजनीतिक कयासों को तो जन्म दे ही दिया है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र में हो रही राजनीति के चार पहलू नजर आते हैं, जिनका प्रभाव राष्ट्रव्यापी हो सकता है। पहला, अपने बयान से क्या शरद पवार कांग्रेस को मजबूत करके उसे भाजपा के समक्ष खड़ा करना चाहते हैं? वे स्वयं भी कांग्रेस से निकले हैं। यह तभी संभव है जब तमाम छोटे-बड़े क्षेत्रीय दल कांग्रेस से जुड़ें और यूपीए-3 की कल्पना साकार हो क्योंकि भाजपा के राजनीतिक अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकने की क्षमता यूपीए में है, जिसे 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व में यूपीए ने साबित किया है। दूसरा, क्या शरद पवार ने अपनी मान्यता के विरुद्ध जाकर राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने का मन बना लिया है? ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ वर्षों पूर्व उन्होंने राहुल गांधी में निरंतरता की कमी का हवाला दिया था। तो क्या यह माना जाए कि राहुल गांधी की जो छवि बना दी गई थी, वे अब उससे निकल चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनसे बेहतर नेता राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है? तीसरा, भाजपा द्वारा छोटे-बड़े क्षेत्रीय दलों में टूट का जो आरोप विपक्षी लगाते हैं, उससे भी शरद पवार सभी को संकेत देने का प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा के साथ टुकड़ों में जाकर अपने अस्तित्व को मिटाने से अच्छा है कि कांग्रेस में शामिल होकर उसे मजबूती दी जाए। आखिरकार, अधिकांश क्षेत्रीय दलों का निर्माण कांग्रेस की गर्भनाल से ही हुआ है। बिहार में पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय इसी मानसिकता का उदाहरण है। भविष्य में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी, आंध्र में वाईएसआर कांग्रेस, कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस, मध्य प्रदेश में बाप-जयस जैसे दल यदि कांग्रेस में विलय कर दें तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए क्योंकि भाजपा ने जिस प्रकार इन्हें राजनीति में अप्रासंगिक करना शुरू किया है, उससे इनके अस्तित्व को लेकर सवाल उठने लगे हैं। चौथा और सबसे महत्त्वपूर्व पहलू है, क्या शरद पवार गाहे-बगाहे भाजपा की दो दलीय व्यवस्था के नेरेटिव को धार दे रहे हैं? शरद पवार की राजनीति को देखें तो वह अप्रत्याशित रही है और उनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है। यदि इस पहलू को सही मानें तो यह भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह से बदलने की मंशा है। भारत में गाहे-बगाहे दो दलीय व्यवस्था को लेकर राजनीतिक व सामाजिक रूप से चर्चा होती रहती है। एक बड़े वर्ग का मानना है कि भारत में सैकड़ों राजनीतिक दलों के होने के चलते यहां क्षेत्रवाद, भाषावाद एवं जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। ऐसे लोग भारत में अमेरिका की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाने का हवाला देते हैं जहां समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास केंद्रित हैं किंतु भारत में राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। संविधान सभा ने भारत में शासन की संसदीय प्रणाली का चयन किया क्योंकि यह भारतीय संदर्भ में कारगर थी। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से परिचित था इसलिए संविधान निर्माताओं ने स?थायित्व की जगह जवाबदेही को महत्त्व दिया तथा सरकार को नागरिकों के प्रति जवाबदेह माना अतः तमाम जातीय, भाषा, प्रांत इत्यादि की विसंगतियों के बाद भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यद्यपि भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश राजशाही से ठीक उलट है और यहां राजा के स्थान पर गणतंत्रीय व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की अपनी कमियां हैं जिनमें प्रमुख हैं, गठबंधन की राजनीति, राजनीति में अपराधीकरण, नीतिगत निरंतरता का अभाव आदि किंतु बहुलतावाद की अवधारणा के चलते भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ही कारगर है, जिसके अपने लाभ हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका एक-दूसरे के परस्पर पूरक हैं। लोकतंत्र स्वतंत्र लोक सेवा और गोपनीयता पर आधारित होती है जिसका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य नागरिक अधिकारों को अक्षुण्ण रखना है।

सीटें जीतने का 'माइंड गेम' तेज

अजय बोकिल

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बाद मटन, मंगलसूत्र और पाकिस्तान जैसे मुद्दों के बाद जीतने वाली सीटों की संख्या का 'माइंड गेम' हावी होता दिख रहा है। इसकी शुरुआत तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में इस घोषणा के साथ की थी, कि इस चुनाव में भाजपा 370 तथा एनडीए 400 पार सीटें जीतेगी। तब बहुत से लोगों ने इसे दंभोक्ति के रूप में लिया था। भाजपा और एनडीए सचमुच यह आंकड़ा पार कर पाते हैं या नहीं, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव में जीत की मनोवैज्ञानिक बढ़त की नींव उसी वक्त रख दी गई थी।

जब विपक्ष को देर से यह चाल समझ आई तब उसने पलटवार किया कि आखिर भाजपा को 400 पार चाहिए क्यों? कहा गया कि भाजपा संविधान बदलने के लिए ऐसा चाहती हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों के लिए संविधान का मतलब आरक्षण ही है और जब यह कहा जाने लगा कि भाजपा दरअसल आरक्षण व्यवस्था खत्म करने के लिए 400 पार सीटें चाहती हैं, तो भाजपा को समझ आया कि उसका नारा बूमरेंग हो रहा है, जो आत्मविश्वास का परिचायक कम और विघातक ज्यादा हो सकता है।

जाहिर है ऐसे में ताबड़तोड़ तरीके से विपक्ष के नरेटिव की काट यह कहकर ढूंढी गई कि वह हिंदुओं में ओबीसी, दलित और आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर मुसलमानों को देना चाहता है। जबकि हकीकत यह है कि इस देश में मुसलमानों में भी करीब 41 फीसदी आबादी ओबीसी की है और वह ओबीसी आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था में पहले से आरक्षण की हकदार है। फर्क इतना है कि यह आरक्षण उन्हें जाति के आधार पर मिला है न कि धर्म के आधार पर।

आरक्षण पर भाजपा के इस पलटवार और देश में चौथे चरण के साथ कुल 543 में से 380 सीटों पर मतदान के बाद हार जीत के नए कयास और गणित लगाए जा रहे हैं। अगर भाजपा के दावों को सही मानें तो तुलनात्मक रूप से वो चार चरणों के बाद सरकार बनाने के करीब दिखती है, जबकि विपक्षी दलों का मानना है कि भाजपा हवा में है।

चुनाव की जमीनी हकीकत दूसरी है वोटर भाजपा के अहंकारी शासन से परेशान है और

चुनाव में उसे हराकर अपनी नाराजगी का इजहार करेगा। लेकिन मामला इतना भी आसान नहीं है। क्योंकि इस देश का मतदाता मौजूदा सरकार को क्यों बदलना चाहता है, इसका भी कोई ठोस कारण उभरकर नहीं आ रहा है, सिवाय महंगाई, बेरोजगारी, जल संकट इत्यादि परंपरागत मुद्दों के। बहरहाल चौथे चरण के मतदान बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से सीटों की जीत के जो दावे हो रहे हैं, उन पर जरा नजर डालें।

देश में सत्ता परिवर्तन का दावा करने वाला इंडिया गठबंधन 466 सीटों पर तो सत्ता में तीसरी बार वापसी का दावा करने वाला भाजपानीत एनडीए कुल 541 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन में भी दो तरह के गठबंधन हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर है और दूसरा क्षेत्रीय स्तर पर है, जिसमें राज्यवार क्षेत्रीय व राष्ट्रीय पार्टियां 233 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन में प्रमुख पार्टी कांग्रेस है, जो खुद 328 सीटों पर ही लड़ रही है, जबकि एनडीए में मुख्य पार्टी भाजपा है, जो खुद 441 सीटों पर चुनाव मैदान में है।

अब चौथे चरण के बाद भाजपा अपने दावों पर कायम है, तो इंडिया गठबंधन के खुद की जीत से ज्यादा भाजपा को हराने के दावे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा नतीजों में 200 से भी कम सीटों तक सिमट जाएगी और इंडिया गठबंधन 315 सीटों पर जीतेगा। शिवसेना (ठाकरे) गुट के उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन 300 से अधिक सीटें जीतेगा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी का दावा है कि इंडिया गठबंधन अकेले यूपी में 50 से ज्यादा जीतेगा तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 'राजनीतिक जोक' के अंदाज में दावा किया कि यूपी में इंडिया गठबंधन 80 में से 79 सीटें जीतेगा केवल एक सीट (वाराणसी) 'मुकाबले' में है। उन्होंने यह भी कहा कि देश की 140 करोड़ जनता भाजपा को 140 सीटों तक समेट देगी। यह शायद मोदी द्वारा 370 सीटें जीतने के दावे का अखिलेशी जवाब था। यानी आंकड़ों की तुकबंदी।

सबसे हैरानी भरा दावा तो बिहार के सीएम नीतीश कुमार का रहा। उन्होंने एक सभा में मंच से पहले तो चार लाख फिर चार हजार और बाद में एनडीए के चार सौ सीटें जीतने की बात कही। हालांकि लोगों ने उनकी बढ़ती उम्र के मद्देनजर इसे जबान फिसलना मानकर अनदेखा किया। इसके अलावा चौथे चरण के मतदान के पहले जेल से छूटे अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर एक 'फार्मूला बम' फोड़ा कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। वजह 75 पार का वो फॉर्मूला है, जो उन्होंने पिछले चुनाव में पार्टी के ही कुछ दूसरे नेताओं को 'निपटाने' के लिए लागू किया था।

केजरीवाल ने यह भी दावे से कहा कि अगले पीएम अमित शाह होने वाले हैं। केजरीवाल को यह जानकारी कहां से मिली पता नहीं, लेकिन इससे दावे से भाजपा में अंदरखाने जरूर खलबली मच गई। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तत्काल इसका खंडन किया कि वह तथाकथित अघोषित फार्मूला मोदी पर लागू नहीं होता। वो 2024 ही नहीं, 2029 में भी प्रधानमंत्री बनेंगे। यानी यह सीटें जीतने के माइंड गेम की नई चाल है। इस दावे ने विपक्ष से ज्यादा उन भाजपा नेताओं का टेंशन जरूर बढ़ा दिया है, जो पार्टी में प्रमोशन की आस लंबे समय से लगाए बैठे हैं।

अगर सीटें जीतने के दोनो गठबंधनों की सत्यता की पड़ताल करें तो एनडीए गठबंधन व्यावहारिकता के ज्यादा नजदीक लगता है। इसका कारण यह है कि एनडीए की मुख्य पार्टी भाजपा में मतदान और नतीजों के आकलन का अपना आंतरिक और पुख्ता सिस्टम है, जो हाईकमान को रिपोर्ट करता है। पार्टी को भरोसा है कि इस बार तुलनात्मक रूप से वोटिंग भले कम हुआ हो, लेकिन भाजपा के वोट ज्यादातर डल गए हैं। ऐसे में जीत का अंतर घट सकता है, लेकिन परिणामों में बहुत अंतर नहीं आएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में नतीजों के पूर्वाकलन का कोई ठोस सिस्टम नहीं है। कार्यकर्ताओं और पोलिंग एजेंटों के फीड, चुनाव सभाओं में भीड़ और राजनीतिक महत्वाकांक्षा आदि के आधार पर संभावित नतीजों का आकलन ज्यादा किया जाता है।

इस चुनाव में तीन चरणों का मतदान अभी बाकी है। लेकिन देश में नई सरकार किसकी बनेगी, यह काफी कुछ उत्तर प्रदेश में सीटों की जीत से तय होगा। यूपी में सर्वाधिक 80 लोकसभा सीटें हैं। प्रधानमंत्री पद के दो दावेदार और वर्तमान पीएम भी इसी राज्य से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर यूपी में इंडिया गठबंधन के 50 से लेकर 79 तक सीटें जीतने के बंपर दावों की पड़ताल करें तो यह कहीं से भी संभव नहीं दिखता। कारण वहां दलों का अलायंस और उनका वोट बैंक है।

राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा (एनडीए गठबंधन) का कुल (पिछले लोकसभा चुनाव के आधार पर) वोट प्रतिशत लगभग 54 फीसदी बनता है, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन का वोट शेयर 23 फीसदी ही होता है। एक और बड़ी पार्टी बसपा है, जिसका पक्का वोट शेयर 19.43 फीसदी है और जो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यूपी में चुनाव नतीजों की असली गेम चेंजर बसपा ही है। बसपा जिस गठबंधन के ज्यादा वोट काटेगी, वही घाटे में रहेगा। वैसे बसपा प्रमुख मायावती की सभी चुनावी चालें भाजपा को लाभ पहुंचाती ज्यादा लगती है। लेकिन वह दुधारी तलवार भी है। क्योंकि मायावती ने इस बार लोकसभा चुनाव में 23 मुसलमानो और 14 ब्राह्मणों को टिकट दिए हैं। ये प्रत्याशी खुद भले न जीतें, लेकिन किसी को भी हार के गड्ढे में धकेल सकते हैं। इस मायने में मायावती का माइंड गेम सबसे अलग और रहस्यमय है। फिर भी यूपी में भाजपा वर्तमान 61 सीटों के नीचे जाएगी, इस बात की संभावना काफी कम है। हालांकि पिक्चर अभी बाकी है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

योगचूडामणि उपनिषद् (भाग-4)

गतांक से आगे...

ऊर्ध्ववायु (डकार) में नाग नामक उपप्राण, आँखों की पलक झपकने में कूर्मवायु, कृकल छींकने में एवं देवदत्त की स्थिति जंभाई लेने में होती है।

सम्पूर्ण शरीर में धनञ्जय वायु इस प्रकार से व्याप्त है कि मृत्यु के बाद भी शरीर को नहीं छोड़ता है। इन्हीं नाड़ियों में जीव (प्राण) भ्रमण करते रहते हैं।

खिलाड़ियों के द्वारा इधर से उधर फेंकी हुई गेंद की तरह जीव भी प्राण, अपान आदि वायुओं से स्थिर नहीं रह पाता अर्थात् सदैव गतिशील रहता है। यह जीव प्राणादि वायुओं के वशीभूत होकर नीचे ऊपर गमन करता हुआ बायें एवं दायें मार्ग में भी आता-जाता है। गमनचक्र तीव्रता से चलने के कारण वह दिखाई नहीं पड़ता।

रस्सी से बँधा हुआ श्येन पक्षी ऊपर उड़ता हुआ भी जिस प्रकार खींच लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार गुणों से आबद्ध यह जीव भी प्राण और अपान वायुओं के द्वारा खींचा जाता है।

प्राण अपान को खींचता है एवं अपान प्राण को खींचता है, इसलिए यह जीव प्राण और अपान की इस क्रिया के द्वारा निरंतर ऊपर-नीचे आता जाता रहता है।

प्राण एवं जीव की इस अधः एवं ऊर्ध्वगमन प्रक्रिया को जानने वाला ही योगवेत्ता है। श्वास स कार ध्वनि (वायु) के माध्यम से भीतर और ह कार के साथ बाहर आती है। इस तरह यह जीव हंस-हंस (हंसमंत्र) का जप सदैव करता रहता है। दिन-रात निरन्तर जप करते रहने से यह जीव इक्कीस हजार छः सौ मंत्र नित्य जपता है।

योगियों के लिए मुक्ति प्रदात्री यही अजपा गायत्री है। इसके संकल्प मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके समान न कोई विद्या, न कोई जप, न कोई ज्ञान पहले हुआ है और न भविष्य में होगा।

क्रमशः ...

विश्व दूरसंचार दिवस

शिवानी कोटनाला

पृथ्वी पर जीवन जीने के लिए संचार का महत्व हमेशा से रहा है। एक व्यक्ति अपनी बात, विचार, मत और इच्छाओं को बताने के लिए संचार के अलग-अलग माध्यमों का इस्तेमाल करता है। डिजिटल युग में संचार के बहुत से माध्यम मिलते हैं। रियल ही नहीं, वर्चुअल वर्ल्ड के जरिए भी हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में एक बड़ी मदद मिलती है।

इसी कड़ी में हर साल 17 मई का दिन विश्न दूरसंचार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंटरनेट और संचार के दूसरे साधनों का समाज में व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसी व्यापक प्रभाव की जागरुकता के लिए विश्न दूरसंचार दिवस हर साल मनाया जाता है। दुनिया भर में अभी भी ऐसे बहुत से देश हैं, जहां लोगों को एक-

दूसरे से जुड़ने में कई बाधाएं आती हैं। संचार में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए ही अंतरराष्ट्रीय संचार संघ की स्थापना अहम मानी जाती है।

विश्न दूरसंचार दिवस के इतिहास पर नजर डालें तो यह दिन साल 1969 से हर साल मनाया जा रहा है। दरअसल 17 मई का दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि इसी दिन साल 1865 को अंतरराष्ट्रीय संचार संघ की स्थापना हुई थी।

आईटीयू का मूल नाम पहले अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ था। पेरिस में पहले अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर के साथ ही आईटीयू की स्थापना हुई थी। साल 1932 में इसका नाम अंतरराष्ट्रीय संचार संघ कर दिया गया, जबकि साल 1947 को यह संघ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में नई पहचान के साथ आया।

मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 मई की तारीख को विश्व सूचना समाज दिवस के रूप में भी घोषित किया गया था। इसी के साथ 17 मई की तारीख विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस के रूप में मनाया जाता है।

यह दिन कम विकसित देशों में डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए मनाया जाता है। हर साल विश्व दूरसंचार दिवस पर, आईटीयू निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों से पार्टनर2कनेक्ट डिजिटल गठबंधन के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह करता है।

दूरसंचार के इस माध्यम ने जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नही छोड़ा जो अछूता हो। मनोरंजन के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी, व्यापार, कृषि, रोजगार, उद्योग, पर्यावरण आदि क्षेत्रों में बहुआयामी जागरूकता और विकास के साथ-साथ संस्कृति संरक्षण, धर्म एवं आध्यात्म का वातावरण बनाने का प्रभावी माध्यम बन गया है। अनेक वेब साइट और एप्स हैं विभिन्न जानकारी प्राप्त करने के लिए। चैनल्स पर निरंतर नवीन समाचारों का प्रसारण होता रहता हैं।

इंटरनेट माध्यम जहां जीवनशैली में वरदान के रूप में जुड़ गया वही इस से साइबर क्राइम, अश्लीलता जैसी चुनोतियाँ भी सामने हैं। हमें इनसे सावधान रह कर अफवाहों से भी बचना होगा।

पीओके के हाथ से निकल जाने के डर से सहमा पाकिस्तान

ललित गर्ग

पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में पाकिस्तान सरकार की तानाशाही, उदासीनता, उपेक्षा एवं दोगली नीतियों के कारण हालात बेकाबू, अराजक एवं हिंसक हो गये हैं। जीवन निर्वाह की जरूरतों को पूरा न कर पाने से जनता में भारी आक्रोश एवं सरकार के खिलाफ नाराजगी चरम सीमा पर पहुंच गयी है। गेहूं के आटे और बिजली की ऊंची कीमतों के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों एवं सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पों में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गयी जबकि 100 से अधिक लोग घायल हो गए। घायलों में अधिकतर पुलिसकर्मी हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान सरकार की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर हैं। पाकिस्तान को पीओके के हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा था। पीओके की आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया है एवं आन्दोलनकारियों को दबाने की दमनकारी कोशिशें की जा रही है। पीओके के बगावती तेवर देख पाकिस्तान के हाथ-पांव फूल गये हैं।

दरअसल, अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के कब्जे के बाद से ही पीओके लगातार सरकार की उपेक्षा, उत्पीडन एवं उदासीनता झेल रहा है। उसकी समस्याओं और विकास पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तान का जोर वहां आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप खोलने पर ज्यादा रहा। पाकिस्तान की सरकार ने पीओके का इस्तेमाल भारत में अशांति, आतंक एवं हिंसा फैलाने के लिये किया है, वह पीओके के माध्यम से कश्मीर को हडपने की हर संभव कोशिश करता रहा है, लेकिन वहां के निवासियों की जरूरतों पर कभी ध्यान नहीं किया। यूं तो अभी समूचे पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हैं, गरीबी, महंगाई एवं आर्थिक दिवालियापन से घिरा है,

दुनियाभर से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिये झोली लिये घूम रहा पाकिस्तान भारत में अशांति एवं आतंक फैलाने से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल, पाकिस्तानी कमरतोड़ महंगाई एवं जनसुविधाओं से जूझ रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 3 अरब डॉलर के कर्ज की मंजूरी देते समय कड़ी शर्तों लगाई थीं, जिसके कारण स्थिति और खराब हो गई है। बिजली दरों में बढ़ोतरी से दिक्कतें बढ़ गई हैं और पाकिस्तान में लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। इन्हीं जर्जर एवं जटिल हालातों के बीच पीओके के हालात पाकिस्तान के लिये नया सिर दर्द बन गया है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों के मुजफराबाद मार्च को दबाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन उतना ही उग्र हो रहा है। पीओके की अवामी एक्शन कमेटी के मार्च और धरने के आह्वान के बाद बेकाबू होते हालात 1955 के अवज्ञा आंदोलन की यादें ताजा कर रहे हैं, जब पीओके के लोगों और पाकिस्तानी फौज में सीधा टकराव हुआ था। अब फिर पीओके के लोगों के उबलते गुस्से ने पाकिस्तानी हुकूमत के माथे पर बल बढ़ा दिए हैं, समस्या को अनियंत्रित एवं अनिश्चित हालात में पहुंचा दिया है।

पीओके के सबसे उत्तरी इलाके गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। पीओके में आजादी के नारे लगने एवं उसे लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग के बाद शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना दोनों सकते में है। पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ पीओकी की जनता जिस तरह खड़ी हो गई, उसने पाकिस्तानी नीति निर्माताओं को तनाव में ला दिया है। हजारों की संख्या में कश्मीरी लोग पीओके में जगह-जगह सड़कों पर उतर आए तो पाकिस्तान को पीओके के हाथ से निकल जाने का डर सताने लगा है। पीओके में विरोध को दबाने के लिए पाकिस्तानी दमन चक्र शुरू हो गया है। इसमें पाकिस्तान रेंजर्स और फ्रंटियर कोर को भी लगाया गया है। पीओके के सभी 10 जिलों में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं। भाजपा की मोदी सरकार के मुख्य एजेंडे में पीओके को पाकिस्तान से मुक्त कराकर भारत में शामिल करना पहले से निश्चित है। पीओके का ताजा संघर्ष एवं आन्दोलन भाजपा की राह को निश्चित ही आसान करेंगी।

भारत के विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान द्वारा जम्मू और कश्मीर की रियासत पर आक्रमण करने के बाद पीओके बनाया गया था। पाकिस्तानी सेना और आदिवासी हमलावरों के हमले के तहत, महाराजा हरिसिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी, जिसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पूरी रियासत पर कब्जा करने से रोक दिया। अब, लगभग सात-आठ दशक से अधिक समय के बाद, जबकि पाकिस्तान भारी वित्तीय, राजनीतिक और मानवीय संकट में फंस गया है, जबकि भारत अपने आर्थिक, राजनैतिक और वैज्ञानिक मापदंडों में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अपनी सैन्य शक्ति को सशक्त कर रहा है। जम्मू-कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है, वहां के लोग शांति, शिक्षा, व्यापार एवं विकास की दृष्टि से नये कीर्तिमान गढ़ रहे हैं जबकि पीओके कम मानव विकास के साथ आर्थिक प्रगति से वंचित जनजीवन से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। स्वयं को ठगा महसूस करते हुए पीओके की आम जनता अब शांति चाहती है, अमन चाहती है, विकास चाहती है, जोकि पाकिस्तान में रहते हुए असंभव है।

दोगली नीतियों के चलते पीओके के प्राकृतिक संसाधनों का पाकिस्तान खुलकर दोहन करता रहा, जबकि वहां के लोग ईंधन, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा और जरूरी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते रहे। पीओके के लोगों ने मई 2023 में बिजली की ऊंची दरों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जो एक साल बाद अब उग्र रूप ले चुका है। आंदोलन से काफी पहले पीओके के लोगों का भारत के प्रति झुकाव समय-समय पर मुखर होता रहा है। पाकिस्तान की राजनीति की दूषित हवाओं ने पीओके की चेतना एवं सोच को आन्दोलनकारी बना दिया है। पिछले साल पीओके और गिलगित के लोगों ने पाकिस्तान की भेदभाव वाली नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने इलाकों को भारत के साथ मिलाने को ही अपने हित एवं शांतिपूर्ण जीवन के अनुरूप मानने लगे हैं। इसके लिये किये गये तब के प्रदर्शन के सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वहां के लोग 'आर-पार जोड़ दो, करगिल को खोल दो' जैसे नारे लगाते नजर आए थे।

पीओके के लोग चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का भी विरोध कर रहे हैं। पीओके में विरोध प्रदर्शन के दौरान जिस तरह भारतीय तिरंगा लहराया जा रहा है और भारत में विलय के स्वर उठ रहे हैं, उससे भविष्य में इस विवादित क्षेत्र पर निर्णायक पटकथा लिखे जाने के आसार नजर आ रहे हैं। भारत को पीओके के घटनाक्रम पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, ताकि इससे हमारे सुरक्षा हितों पर प्रतिकूल असर न पड़े एवं भविष्य की नीतियों का निर्धारण करने में सुविधा रहे।

आज का इतिहास

1756 ब्रिटेन ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।
1782 ग्रेट ब्रिटेन की संसद ने आयरलैंड अधिनियम की निर्भरता को सुरक्षित करने के लिए अधिनियम के निरसन को पारित किया।
1792 न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत से, बटनवुड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
1792 चौबीस स्टॉक ब्रोकर्स ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बटनवुड समझौते पर हस्ताक्षर किए।
1814 नॉर्वे के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और नॉर्वे की संविधान सभा द्वारा क्रिश्चियन फ्रेडरिक को नॉर्वे का नया राजा चुना गया।
1863 रोसालिया डी कास्त्रो ने कैंट्रेस गैलीगोस, उनकी कविता का एक संग्रह, गैलिशियन् भाषा में पहली पुस्तक प्रकाशित की।
1865 इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की स्थापना की गयी।
1865 इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन, एक अंतर्राष्ट्रीयकरण, जो अंतर्राष्ट्रीय रेडियो और प्रौद्योगिकी को मानकीकृत और नियंत्रित करता है, को इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन इनपैरिस के रूप में स्थापित किया गया था।
1884 अलास्का को एक अमेरिकी क्षेत्र में मिलाया गया।
1900 चीन में बॉक्सर्स द्वारा पेकिंग के 100 मील के भीतर तीन गांवों को जला दिया जिसमे 60 चीनी और क्रिश्चियन नागरिक मारे गए।
1902 एंटीकाइथेरा तंत्र, सबसे पुराना ज्ञात जीवित गियरडैमचैनिज्म है, जिसे एंटीकाइथेरा के ग्रीक द्वीप के एक जहाज से उतरने वाली कलाकृतियों के बीच खोजा गया था।
1909 प्रथम गिरो डी टालिया साइकिल दौड़ मिलान शहर में शुरू हुई, जिसमें लुइगी गन्ना विजेता हुए।
1914 अल्बानिया ने आधिकारिक तौर पर उत्तरी एपिरस के क्षेत्र को अल्बानियाई राज्य के साथ एक अनौपचारिक क्षेत्र के रूप में मान्यता दी, जो प्रथम विश्व युद्ध के कारण कभी स्थापित नहीं हुआ था।
1933 नार्वे की फासीवादी पार्टी नस्जोनल समलिंग की स्थापना 17 मई, 1933 को विदकुन क्विसलिंग और जोहान बर्नहार्ड हेजोर्ट द्वारा की गई थी। इसने इस तथ्य के बावजूद नार्वे की राजनीति पर भारी प्रभाव डाला कि इसने 2.5% से अधिक मत कभी हासिल नहीं किए और अंततः 1945 में भंग हो गया।
1973 राष्ट्रपति अभियान गतिविधियों पर सीनेट की चयन समिति ने 17 मई, 1973 को वाशिंगटन डी.सी. में वाटरगेट घोटाले की सुनवाई शुरू की।

भारत का ईरान से एक डील ने कैसे बढ़ाई 3 देशों की धड़कनें

अभिनय आकाश

भारत की विदेश नीति का सबसे पहला मंत्रा क्या है? पहला मंत्र यही है कि हमेशा देश का हित सबसे ऊपर और सबसे पहले रहेगा। इसलिए अमेरिका के ना चाहते हुए भी ईरान के चाबहार पोर्ट पर भारत ने तिरंगा लहरा दिया है। लेकिन खुद को दुनिया का चौकीदार समझने वाला अमेरिका तिलमिला गया है और उसने प्रतिबंध की धमकी दे दी है। चाबहार पर भारत के फैसले का एक मतलब ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे पर अमेरिका की एक न सुनी और यही अमेरिका की तिलमिलाहट की सबसे बड़ी वजह भी है। चाबहार ईरान का एक मात्र डीप सी पोर्ट यानी गहरे समुद्र में मौजूद बंदरगाह है। इस समझौते को पाकिस्तान और चीन के लिए भी झटके के तौर पर देखा जा रहा है।

भारत ने ईरान के चाबहार में स्थित शाहिद बेहश्ती बंदरगाह टर्मिनल के परिचालन के लिए सोमवार को 10-वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इससे भारत को मध्य एशिया के साथ कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी। चाबहार बंदरगाह ईरान के दक्षिणी तट पर सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। इस बंदरगाह को भारत और ईरान मिलकर विकसित कर रहे हैं। बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और ईरान के पोर्ट्स एंड मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापारिक सौदे करने वाले किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाए जाने का संभावित खतरा है। उसने यह भी कहा कि वह जानता है कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से जुड़े एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हम इन खबरों से अवगत हैं कि ईरान और भारत ने चाबहार बंदरगाह से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं चाहूंगा कि भारत सरकार चाबहार बंदरगाह और ईरान के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों पर बात करे। सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह को लेकर ईरान के साथ भारत के समझौते के बारे में एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चूंकि यह अमेरिका से संबंधित है, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू हैं और हम उन्हें बरकरार रखेंगे।

अमेरिका इसे न्यू डील के तौर पर देख रहा है। साल 2018 में अमेरिका में रिब्लिकन रूल था और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। ट्रंप अक्सर धमकियों के जरिए भारत को डराने की कोशिश समय समय पर करते रहते थे। चाहे वो एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो या चाबहार पोर्ट से जुड़ा मसला या फिर कोविड-19 के वक्त दवाई की बात हो। ट्रंप की तरफ से कितनी बार कहा गया कि प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, या कोई कार्रवाई की जा सकती है। एक बार तो लग रहा था कि चाबहार और रूस से एस 400 की खरीद के बाद भारत पर कुछ बंदिशें

लग सकती हैं। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी इतनी अच्छी थी। इसके साथ ही भारत की जरूरत अमेरिका को इतनी ज्यादा थी कि वो किसी भी किस्म की कार्रवाई से बचता रहा। ईरान के ऊपर अमेरिका ने बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। उसकी वजह से भारत वहां पर इनवेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा था। भारत ने अमेरिका से बातचीत कर इसमें राहत पा ली थी। लेकिन वर्तमान में अमेरिका की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि उस वक्त मिली राहत 2018 तक के इनवेस्टमेंट के लिए ही था। अब भारत ने नई डील साइन की है कि 10 साल के लिए पूरा चाबहार पोर्ट इंडियन पोर्ट ऑथरिटी को मिल जाएगा। इसे अमेरिका एक नई डील की तरह देख रहा है और भारत पर प्रतिबंध की बात कर रहा है।

भारतीय मीडिया अमेरिका के कदम को लेकर तरह-तरह की आशंकाएं जता रहा है। व्हाइट हाउस को ही इस पर फाइनल डीसिजन लेना है। लेकिन ताजा घटनाक्रम में ईरानी राजदूत इलाही ने बयान देते हुए कहा कि भारत दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका के लिए भी बहुत जरूरी है और वो भारत पर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगा पाएगा। चाबहार पोर्ट भारत डेवलप कर रहा है। लेकिन ये कही पर लिखा नहीं है कि चाबहार पोर्ट केवल भारत ही इस्तेमाल करेगा। चाहे तो ये पोर्ट कल को ओमान, यूएई, सऊदी अरब, रूस, अर्मेनिया भी चाबहार को इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका अगर चाबहार पोर्ट को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाता है तो इससे न केवल भारत नाराज होगा। इससे सेंट्रल एशियान देश नाराज होगा। रूस भी नाराज होगा। रूस और सेंट्रल एशिया समेत कई देशों के लिए भारत तक पहुंचने का रास्ता चाबहार पोर्ट से ही जाता है। ईरान के राजदूत ने कहा कि अगर अमेरिका प्रोजेक्ट पर किसी तरह का बैन लगाता है तो पूरे रीजन में कई देशों को इससे नुकसान होगा। ये अमेरिका को भारी पड़ सकता है।

चाबहार पोर्ट को अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के एक अहम सेंटर की पेश किया गया है। यह प्रॉजेक्ट भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप के बीच माल-ढुलाई के लिए 7,200 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है। सरकार ने साल 2024- 2025 के लिए चाबहार के लिए 100 करोड़ आवंटित भी किए थे।

बंदरगाह को इंटरनैशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ जोड़े जाने के बाद भारत की कनेक्टिविटी ईरान के जरिए सीधे रूस तक होगी। इससे पाकिस्तान को बायपास कर अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बन जाएगी।

इंटरनैशनल नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर में रूस की अहम भूमिका है। इससे एक ओर आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देश कनेक्ट होंगे तो दूसरी ओर अफगानिस्तान और ईरान। इसके अलावा ईरान भी एक रेल लाइन लेकर आने वाला है, जो चाबहार से शुरू होकर अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाएगी। इससे ईरान को भी भारत के जरिए साउथ एशिया में कनेक्टिविटी हासिल होगी। भारत ऐसी कनेक्टिविटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिससे कि हमारा सामान रोड और शिप के रास्ते सेंट्रल एशिया होते हुए रूस और यूरोप पहुंचेगा। ईरान इस तरह की कनेक्टिविटी से दूसरे देशों को पहले भी जोड़ चुका है। ईरान चाहता है कि एक संतुलन जरूरी है ताकि पूरी निर्भरता चीन पर ना हो।

चीन ने समुद्र में उतार दिया पहला सुपरकैरियर युद्धपोत फुजियान

चीन ने अपना फुजियान अब पानी में उतार दिया है। समुद्र में इसकी टेस्टिंग हो रही है कि आखिर ये कितना बलशाली और कितना ताकतवर है। शंघाई के समुद्री सुरक्षा प्रशासन के अनुसार, इसका मूल्यांकन जियांगन शिपयार्ड से लगभग 130 किलोमीटर दूर पूर्वी चीन सागर में होने की उम्मीद है, जहां वाहक छह साल से अधिक समय से निर्माणाधीन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापोल्ट्स से लैस चीन का पहला सुपरकैरियर माना जाने वाला यह युद्धपोत चांगक्सिंग द्वीप पर जियांगनान में अपनी बर्थ से रवाना हुआ था। इस चीनी युद्धपोत को अमेरिकी नौसेना के गेराल्ड आरफोर्ड के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट में सैन्य विशेषज्ञों का हवाला देते हुए कहा गया है कि परीक्षणों में कम से कम एक साल और लगेगा, पहले चरण में बिजली, नेविगेशन और संचार प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चीन के इस कदम के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या फुजियान दुनिया के सबसे बेहतरीन युद्धपोतों में से एक है। दुनिया के महासागरों पर फ़ुज़ियान के आगमन का नौसैनिक शक्ति संतुलन के लिए क्या मतलब है? इसकी तुलना भारत के विमानवाहक पोत से कैसे की जाती है? फ़ुज़ियान का नाम ताइवान के सामने चीन के दक्षिण-पूर्वी तट पर स्थित फ़ुज़ियान प्रांत के नाम पर रखा गया है। यह तीसरा वाहक लियाओनिंग और शेडोंग प्रांतों के नाम पर चीन की पुरानी परंपरा का पालन करता है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की योजना 2035 तक कुल छह वाहक बनाने की है, जो इसे अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ब्लू-वॉटर नेवी बना देगी। फ़ुज़ियान चीन का सबसे उन्नत विमानवाहक पोत है और इसे चाइना स्टेट शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया गया। फ़ुज़ियान को चीन का सुपरकैरियर कहा जाता है, जो पिछले दो की तुलना में अधिक उन्नत है। यह लगभग 1,035 फीट लंबा है, और लगभग 80,000 टन भार को विस्थापित करता है। विक्रांत की सबसे बड़ी खासियत इसका स्वदेशी होना है। विक्रांत के 70% से भी ज्यादा मटेरियल और इक्विपमेंट भारत में ही बनाए गए हैं। इसी के साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की क्षमता है। कैरियर की डिजाइनिंग से लेकर असेंबलिंग तक का सारा काम कोच्चि के शिपयार्ड में किया गया है। इसका पूरा जिम्मा डायरेक्ट्रेट ऑफ नेवल डिजाइन (डीएनडी) के पास है। साथ ही कैरियर का निर्माण आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। इस वजह से इसकी कुल लागत (23 हजार करोड़) का 80-85% हिस्सा भारतीय मार्केट में ही खर्च हुआ है। विक्रांत- 262 मीटर लंबा, 62 मीटर चौड़ा। फुजियान- 320 मीटर लंबा, 72 मीटर चौड़ा है।

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रदर्शन

जे सुशील

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में छात्रों के प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। करीब तीन हफ्ते पहले कुछ संस्थानों से शुरू हुए इन प्रदर्शनों के दौरान कई छात्रों और प्रोफेसरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कई परिसरों में अभी भी छात्रों ने तंबू लगाकर प्रदर्शन जारी रखा है। इन प्रदर्शनों का संबंध पिछले साल अक्तूबर में हुई घटना से है, जिसमें फिलिस्तीनी गुटों ने इस्राइली इलाके में हमला किया था।

इसके बाद इस्राइली कार्रवाई में गाजा पट्टी में अब तक हजारों फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इस्राइल की इस लगातार चल रही कार्रवाई की न तो अमेरिका ने आलोचना की है और न ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे रोकने के लिए कोई गंभीर प्रयास हुए हैं। अमेरिकी सरकार पूर्व के अपने रवैये की तर्ज पर इस्राइल का समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने गाजा में मानवीय संकट होने की बात मानी है, लेकिन वे इस्राइल के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई करने के पक्ष में हैं और न ही उसकी मनमानी रोकने के। यही हाल राष्ट्रपति चुनाव में उनको चुनौती दे रहे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का भी है। इसकी एक वजह अमेरिकी राजनीति में इस्राइल समर्थक व्यवसायियों और अन्य समूहों से मिलने वाला अकूत धन है। येरुशलम पोस्ट अखबार की 2018 की एक खबर पर यकीन करें, तो डेमोक्रेटिक पार्टी को मिलने वाले चंदे का पचास प्रतिशत ऐसे लोगों से आता है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी को मिलने वाले चंदे में उनका योगदान पच्चीस प्रतिशत है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेरिका में उनका कितना महत्व है। लेकिन मामला यहीं पर खत्म नहीं होता है। अमेरिका के कई बड़े व्यवसाय और संस्थान इस्राइल समर्थक चलाते हैं और उनके तार हर सरकार से जुड़े होते हैं।

फिलिस्तीन में हो रही व्यापक इस्राइली कार्रवाई पर अमेरिकी सरकार की चुप्पी से अमेरिकी विश्वविद्यालयों के छात्र बेहद नाराज हैं और वे इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि कम से कम विश्वविद्यालय उन व्यवसायों में किया गया अपना निवेश वापस लें, जो हथियारों के धंधे से जुड़ी हैं और जिन्हें गाजा

में हो रही लड़ाई से लाभ पहुंच रहा है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि अमेरिका के ज्यादातर बड़े विश्वविद्यालय प्राइवेट संस्थान हैं, मसलन- कोलंबिया, प्रिंस्टन, हॉर्वर्ड, एमआइटी आदि, और इन सभी में पिछले कुछ हफ्तों से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों के पास एक बड़ी राशि होती है, जिसका वे निवेश करते हैं और इससे मिलने वाले लाभ से संस्थान चलाया जाता है। छात्र जो फीस देते हैं, वह भी यूनिवर्सिटी चलाने के काम आता है, यानी एक तरह से विश्वविद्यालय किसी कॉरपोरेट कंपनी की तरह ही चलते हैं। छात्रों का कहना है कि चूंकि वे एक बड़ी रकम फीस के तौर पर देते हैं, तो उन्हें इस पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है कि यूनिवर्सिटी अपनी रकम का निवेश कैसे करे।

इन प्रदर्शनों की शुरुआत छोटी मांगों से हुई थी और अप्रैल की शुरूआत में कुछ यूनिवर्सिटियों में छात्रों ने तंबू लगाकर विरोध करना शुरू किया था। पहले कुछ दिनों तक तक तंबू लगे रहे, लेकिन जैसे-जैसे इन प्रदर्शनों को प्रोफेसरों, आम लोगों का समर्थन मिलना शुरू हुआ, वैसे-वैसे यूनिवर्सिटियों ने इसके खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू कर दी। न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने तंबूओं को उखाड़ दिया और कई छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। प्रिंस्टन यूनिवर्सिटी में दो छात्रों को निलंबित कर दिया गया। एमआइटी और अन्य संस्थानों में भी छात्रों के कॉलेज परिसर में तंबू लगाने पर रोक लगा दी गयी है और सप्ताहांत में अलग से पुलिस निगरानी हो रही है।

भारत में इन प्रदर्शनों की तस्वीर देखने वाले इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि अमेरिकी पुलिस भी कमोबेश अमेरिकी छात्रों के साथ वैसी ही हिंसा करती है, जैसा भारत में पुलिस करती है। इसका उत्तर बस यह हो सकता है कि पुलिस हर जगह एक जैसी होती है- हिंसक, निर्मम और आदेशों का पालन करने वाली। वह अमेरिका में भी वही कर रही है, जो उनसे सत्ता कह रही है। एमरी यूनिवर्सिटी की एक बुजुर्ग प्रोफेसर को पुलिस ने धक्का दिया और घसीट कर गिरफ्तार किया, जिसकी भारी आलोचना हुई है।

हालांकि ऐसा नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में पुलिस कार्रवाई हुई ही हो। कुछ विश्वविद्यालयों में वहां के कुलपतियों ने न तो पुलिस बुलाया है और न ही छात्रों को हटने को कहा है। वहां के प्रोफेसर और प्रशासन के लोग लगातार छात्रों से बात कर रहे हैं और बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुश्किल काम है क्योंकि मामला निवेश का है। अगर विश्वविद्यालय इस तरह से निवेश का फैसला करने लगेंगे, तो कल को उन्हें डोनेशन मिलने में मुश्किल हो सकती है। इस्राइल समर्थक बड़े दानदाता हैं। वे इन यूनिवर्सिटियों को पैसा देना बंद कर सकते हैं। मूल रूप से मुद्दा पैसे के जोर का है, लेकिन उस बारे में कोई कम ही बात करता है। अंग्रेजी में लिखे गये कुछ लेखों में अमेरिकी छात्रों के प्रदर्शनों को लोकतंत्र के संकट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बदलती परिभाषा आदि से जोड़ा गया, पर ये सब गौण मसले हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि इस्राइल समर्थक पैसा अमेरिकी राजनीति की दशा और दिशा लंबे समय से तय करता रहा है।

मुश्किल यह है कि अगर कोई इस बात को स्पष्टता से कहे, तो उस पर बड़ी ही आसानी से यहूदी-विरोधी या एंटीसेमाइटिक होने का आरोप मढ़ दिया जाता है। ऐसा करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले जर्मनी द्वारा किये गये यहूदी नरसंहार में बचे कुछ यहूदी और उनके परिजन भी गाजा में इस्राइल की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जनसंहार की आड़ लेकर यहूदियों को ऐसा नहीं करना चाहिए और गाजा में शांति बहाली का रास्ता खोजना चाहिए। बहरहाल यह सप्ताह अमेरिकी विश्वविद्यालयों में ग्रैजुएशन वीक है, यानी ग्रैजुएट हो रहे छात्रों को सम्मानित करने का सप्ताह। इस अवसर पर भव्य आयोजन होते हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इन आयोजनों के दौरान कई छात्र फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे।

अगर परमाणु हमला हो गया तो...क्या हम इसके लिए तैयार हैं?

जलज मिश्रा

परमाणु युद्ध का खतरा लगातार बढ़ रहा है। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र अपने हथियार और मिसाइलें बढ़ा रहे हैं। क्या कोई इस विषय में सोच रहा है? आज देश जैसे परमाणु हथियार बना रहे हैं, वे 1945 में अमेरिका द्वारा नागासाकी व हिरोशिमा में बरसाए गए बमों की तुलना में ज्यादा घातक हैं। आज दुनिया एक बड़े खतरे के साये में जी रही है। यह खतरा केवल यूक्रेन ही नहीं, बल्कि फारस की खाड़ी, ताइवान, कोरियाई प्रायद्वीप इत्यादि उन सभी जगहों पर मंडरा रहा है, जहां युद्ध हो सकता है। यह कहानी इस बारे में है कि अगर एक छोटा-सा परमाणु बम भी किसी देश पर गिराया जाए, तो वहां का मंजर कैसा होगा? किसी भी तरह के परमाणु विस्फोट का सामना कर चुके लोगों के साथ सैकड़ों घंटे के साक्षात्कार, परमाणु विस्फोट की मॉडलिंग और विभिन्न तरह के अनुसंधानों के आधार पर हम उस अनुभव के करीब पहुंचे हैं, जो वाकई परमाणु हमले का अनुभव है। परमाणु युद्ध को अक्सर अकल्पनीय बताया जाता है। लेकिन सच यह है कि इसकी कभी ठीक से कल्पना भी नहीं की गई।

अगर आपको परमाणु हमले के भयावह परिणामों की आशंका खतरनाक लगती है, तो जरा विचार करके देखें कि अमेरिका और यूक्रेन की सरकारें कम से कम दो वर्षों से इस परिदृश्य की योजना बना रही हैं। यह बात दरअसल तब की है, जब 2022 खत्म हो रहा था। एक अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यह आशंका जताई थी कि यूक्रेनी सेना को रोकने के लिए रूस उस पर परमाणु हमला करने वाला है। अमेरिका और यूक्रेन तुरंत हरकत में आ गए। यूक्रेन के शहरों और परमाणु संयंत्रों के पास सैकड़ों रेडिएशन डिटेक्टर लगा दिए गए। अमेरिका ने भी हाथ से उपयोग में लाए जाने वाले एक हजार से ज्यादा उपकरण यूक्रेन भेजे। सबसे खराब स्थिति की कल्पना करते हुए यूक्रेन में करीब 200 अस्पतालों को परमाणु हमले की स्थिति में सहायता प्रदान करने वाली सुविधाओं से सुसज्जित किया गया। हजारों डॉक्टरों व नर्सों को रेडिएशन के जोखिम से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। रेडिएशन के असर को कम करने वाली पोटेशियम आयोडाइड की गोलियों के भंडार पूरे देश में एकत्र किए गए।

लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के चार दिन बाद भी जब रूस ने परमाणु हमला नहीं किया, तब बाइडन प्रशासन ने विशेषज्ञों और रणनीतिकारों का एक छोटा-सा समूह बनाया, जिसे 'टाइगर टीम' नाम दिया गया। इस टीम को परमाणु हमले की स्थिति में क्या तैयारियां होनी चाहिए, इस पर एक 'मार्गदर्शिका' तैयार

करनी थी। टाइगर टीम ने खुफिया, सैन्य और नीति क्षेत्रों के विशेषज्ञों से विमर्श करके परमाणु हमलों के मॉडल पर काम करते और वर्षों पुरानी आपातकालीन तैयारी योजनाओं में संशोधन करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें उन बिंदुओं को हटा दिया गया, जो आज साइबर युग में अप्रासंगिक हो गए हैं। टाइगर टीम की रिपोर्ट फिलहाल व्हाइट हाउस के वेस्ट विंग की बगल में आइजनहॉवर कार्यकारी कार्यालय भवन में रखी है। इसमें राष्ट्रपति बाइडन या किसी भी अन्य भावी राष्ट्रपति के लिए राजनयिक और सैन्य विकल्पों की अद्यतन मार्गदर्शिका दी गई है, जो उसी सूरत में काम में आएगी, जब यूक्रेन में परमाणु हमला होता है। इस पूरी कवायद का चौंकाने वाला निष्कर्ष यही है कि परमाणु हमले की आशंका, जो अब तक अकल्पनीय मानी जा रही थी, शीतयुद्ध के बाद अब किसी भी अन्य समय की तुलना में बढ़ गई है। टाइगर टीम के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, 'पिछले तीस साल से जिन्न बोतल में रहा है।' रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अभी पिछले हफ्ते दुनिया को इस अस्तित्वगत खतरे की याद तब दिलाई, जब उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नाटो ने यूक्रेन में अपनी भागीदारी बढ़ाई, तो परमाणु युद्ध होगा। शीतयुद्ध काल के बाद कई पीढ़ियां गुजर गईं, इसलिए परमाणु युद्ध को एक बिसरी हुई कहानी माना जाने लगा था। लेकिन अब इसकी तैयारी के लिए मानवता को जगाने का समय आ गया है।

मिसाइल लॉन्च कर दी गई है। जब इसकी ठोस-ईंधन वाली रॉकेट मोटर सक्रिय हो जाएगी, तो वारहेड वापस पृथ्वी की ओर गिरने लगेगा। और जमीन से कुछ मील ऊपर यह फट जाएगा। इसकी प्लूटोनियम कोर और आसपास की सामग्री इस तरह से एक साथ जुड़ी हुई है कि यह एक मिली सेकंड के भीतर आयनित गैस और फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदल जाएगी। एक चमकदार सफेद रोशनी आकाश को मीलों तक ढक लेगी। जो भी इसे देखेगा, वह कुछ देर के लिए अंधा हो जाएगा। 10 हजार टन टीएनटी विस्फोटक फट गया हो, ऐसी गर्जना से नीचे की जमीन हिल जाती है। एक विशाल आग का गोला तेजी से फैलने लगता है। और यह सब इतनी जल्दी से होता है, जैसे एक साथ ही सब कुछ हो रहा हो। एकदम से तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है, जो सूर्य की सतह से भी अधिक गर्म होता है। लकड़ी, प्लास्टिक, तेल इत्यादि ज्वलनशील चीजें आग को भड़काती हैं और जानवर आग की लपटों से घिर जाते हैं। फिर कुछ ही सेकंडों में वे राख में तब्दील हो जाते हैं। गैसें और गिरे हुए बिजली के तार इस नर्क को मीलों तक भड़काने का काम करते हैं। आग का तूफान इतनी अधिक ऑक्सीजन की खपत करता है कि इससे कारों या घरों के अंदर छिपे लोगों का दम घुट सकता है।

फिर एक शॉक वेव आती है। भरपूर गड़गड़ाहट के साथ एक ऊर्जा, जो हर दिशा में फैल जाती है और सुपरसोनिक की गति से दौड़ती है। इमारतें, पेड़ और अन्य सभी चीजें टूटने लगती हैं और एक-दूसरे पर चढ़ने लगती हैं। वस्तुएं, इमारतें, पेड़, जानवर और इंसान सब जल चुके हैं। डामर, स्टील, मिट्टी, कांच, मांस और हड्डियों का मलबा उड़कर मीलों तक फैले मशरूम की आकृति के बादलों, जो जमीन से लेकर आसमान तक व्याप्त है, में समा गया है। जमीन से आकाश तक फैला बादलों का तूफान एक जीवित वस्तु की तरह प्रतीत होता है। इसका रंग आकाश में तब तक सफेद से पीला, लाल से काला होता रहता है, जब तक यह सूर्य को ढक न ले। चारों तरफ अंधेरा छा गया है। कानों में घंटियां बज रही हैं। धुएं और मलबे से हवा घनी हो चुकी है। जो लोग बच गए हैं, उन पर रेडिएशन का असर उल्टी और दस्त के दौरों के रूप में होता है। जो लोग स्वस्थ दिख रहे हैं, वे कुछ दिन बाद एनीमिया से पीड़ित और कमजोर हो सकते हैं। उनके बाल झड़ सकते हैं, आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली विफल हो सकती है। गर्भवती महिलाओं के गर्भों पर असर पड़ सकता है और पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचा नुकसान वर्षों तक बना रह सकता है। वर्ष 2022 का एक वैज्ञानिक अध्ययन बताता है कि अगर हिरोशिमा में गिराए गए बम के आकार के 100 बम, जो अनुमानित वैश्विक परमाणु शस्त्रागार के एक फीसदी से भी कम हैं, शहरों में गिराए जाते हैं, तो करीब तीन करोड़ लोग तो तुरंत मर सकते हैं और करीब 26 करोड़ लोग दो वर्षों के भीतर भूख से मर सकते हैं।

पाकिस्तान के पास एटम बम है... क्या नए भारत का मिजाज नहीं समझ पाए फारूक

नवीन कुमार पाण्डेय

कोई जरूरी नहीं कि उम्र बीतने के साथ-साथ आपकी समझ भी बढ़ती जाए। संभव है कि आप ताउम्र अपनी समझ को निखारने में नाकामयाब रहें। ऐसी स्थिति के लिए कई बातें जिम्मेदार हो सकती हैं। स्वाभाविक तौर पर कमजोर बुद्धि प्राथमिक कारण हो सकती है, लेकिन कई बार हद से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश में भी मूर्खता आपकी जिंदगी का शगल बन जाती है। एक तीसरी तरह की स्थिति भी होती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में 'एड़ा बनकर पेड़ा खाने' के मुहावरे से परिभाषित किया जाता है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला किन वजहों से लगातार नासमझी का इजहार करते रहते हैं, यह तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन इतना तो सही है कि वो अपने बड़बोलेपन को लेकर बिल्कुल कंस्टिटेंट रहते हैं। अब्दुल्ला हैं कि अपनी भविष्यवाणियों में लगातार मात खाते रहने के बाद भी नए-नए शिगूफे छोड़ने से बाज नहीं आते। फारूक ने फिर वही किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) को वापस लेने का प्रयास हुआ तो पाकिस्तान भारत पर परमाणु बम से हमला कर देगा। उन्होंने पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, 'याद रखें, वो भी (पाकिस्तान ने) चूड़ियां पहने नहीं हैं। उनके पास भी एटम बम है, याद रखें।' उन्होंने आगे कहा, 'अफसोस की बात है कि वह एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा।' अब कौन समझाए कि पाकिस्तान भी अब यह गीदड़ भभकी देना भूल चुका है, लेकिन फारूक अब्दुल्ला भूलने को तैयार नहीं। ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जिन्होंने दावा किया था कि नरेंद्र मोदी एक बार नहीं, दसियों बार भी प्रधानमंत्री बन गए तो आर्टिकल 370 को छू नहीं सकते। लेकिन मोदी ने दूसरी बार सरकार बनते ही जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया और फारूक अब्दुल्ला लंबे समय तक नजरबंदी काटते रहे। पाकिस्तान ने उन्हें तब खूब निराश किया था। फारूक अब्दुल्ला को खूब उम्मीद होगी कि आर्टिकल 370 हटाने पर पाकिस्तान परमाणु बम से भारत पर हमला बोल देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एटम बम से अटैक तो छोड़िए, सामान्य गोली-बारी भी नहीं कर सका। फारूक की तरह ही, जम्मू-कश्मीर की एक और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया तो कश्मीर में खून की नदियां बहेंगी और वहां कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। वो भी लंबे वक्त नजरबंद रही थीं। फारूक को कम-से-कम अपने जैसे ही बड़बोले पाकिस्तानी साथी से कुछ सीख लेना चाहिए था। इमरान खान की सरकार में मंत्री रहे शेख रासिद ने भारत को यह कहकर धमकाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के पास पाव-पाव भर के भी परमाणु बम हैं जो आसानी से भारत पर छोड़े जा सकते हैं। फिर वो मौका भी आ गया कि पाकिस्तान कम से कम वो पाव-पाव भर के परमाणु बम तो छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय सेना ने पहले पीओके के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की, फिर वायु सेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। दोनों कार्रवाइयों में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर दर्जनों आतंकियों को मार गिराया, लेकिन पाकिस्तान का परमाणु बम धरा का धरा रह गया। ये वैसी परिस्थितियां थीं जब पाकिस्तान को अपनी धमकियां सही साबित करने के मौके मिले थे। आखिरकार वह परमाणु बनाने के बाद से ही बात-बेबात भारत को धमकी दिया करता था कि भारत ने उसकी तरफ आंख उठाकर देखा भी तो एटम बम से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आज किस कदर दुर्दशा का शिकार है, यह संभवत: फारूक अब्दुल्ला के सिवा सारे संसार को पता है। दुनियाभर में शायद फारूक ही अकेले वो इंसान होंगे जिन्हें यह भी नहीं पता कि पाकिस्तान को आर्थिक रूप से पंगु करने और दुनिया में अलग-थलग करने के पीछे भारत का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन वो कहते हैं ना कि फारूक या तो बहुत नादान हैं या बहुत चालाक। एड़ा बनकर पेड़ा खाने की उनकी प्रवृत्ति भी पुरानी है। फारूक अब्दुल्ला इन तीनों में किसी भी परिस्थिति के दास हों, पाकिस्तान परस्ती उनकी फितरत बन चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो भारत का ऐतिहासिक स्टैंड ही दुहराया है। फारूक को इससे भला भड़कने की दरकार क्यों आन पड़ी! फारूक अब्दुल्ला एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। वो महान देशभक्त होने का खूब दंभ भरते हैं, लेकिन पाकिस्तान परस्ती छिपा नहीं पाते।

ऋषिकेश के पास हैं ये ऑफबीट जगहें कम पैसों में करें खूब मस्ती

गर्मियों में छुट्टी मनाने जाना चाहते हैं लेकिन किसी ठंडी और कम भीड़भाड़ वाली जगह की तलाश में हैं तो ऋषिकेश के पास कई बेहतर विकल्प मिल जाएंगे। वैसे तो उत्तराखंड में कई हिल स्टेशन हैं, जहां गर्मियों के मौके पर जाया जा सकता है, इसी कारण इस मौसम में पर्यटकों की भीड़ यहां पहुंच जाती है। इस भीड़ से बचना चाहते हैं तो ऋषिकेश के करीब ऑफबीट जगहों पर जाएं। यहां घूमने के लिए खर्च भी बहुत अधिक नहीं आएगा और सिर्फ दो से तीन दिन की छुट्टियों यानी वीकेंड ट्रिप का लुत्फ उठाया जा सकता है।

डोडीताल

उत्तरकाशी जिले अस्सी गंगा क्षेत्र में स्थित है डोडीताल. जहां देश विदेश से पर्यटक और एडवेंचर के शौकीन ट्रैकिंग के लिए आते हैं. ट्रैकिंग के साथ साथ डोडीताल भगवान गणेश की जन्मभूमि भी है.

यहां मां अन्नपूर्णा का मंदिर है जो शीतकाल में बंद रहता और ग्रीष्मकाल में खोल दिया जाता है. माना जाता है कि डोडीताल में इस्नान करने से पूर्व मुख्य द्वार की सुरक्षा के लिए माता पार्वती ने गणेश को जन्म दिया था,इसी लिए डोडीताल को गणेश जन्मभूमी भी कहा जाता है. यहां मां पार्वती की पूजा मां अन्नपूर्णा के रूप में होती है.

कैसे पहुंचे डोडीताल

उत्तरकाशी से डोडीताल पहुंचें के लिए पहले उत्तरकाशी से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंगोरी पहुंचना पड़ता है, जहां से संगमचट्टी करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है. संगमचट्टी के बाद एक सड़क मार्ग और एक ट्रैक मार्ग अगोडा गांव पहुंचता है. सड़क मार्ग से अगोडा की दूरी 15 किलोमीटर है जबकि पैदल ट्रैक 4 किलोमीटर है. अगोडा से ट्रैकिंग एजेंसियों के माध्यम से करीब 16 किलोमीटर के ट्रैक की शुरुवात होती है. अगोडा गांव को डोडीताल ट्रैक का बेस कैंप भी है. समुद्र तल से 3310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डोडीताल ट्रैक की शुरुआत आगोड़ा से होती है. जहां रास्ते मे कई पड़ाव आते हैं जिसमे देवरा- धारकोट ङ्क कछेरु ङ्क मांझी मुख्य पड़ाव हैं. इन जगाहों में ग्रामीणों की छानियां हैं और ग्रामीण रोजगार के लिए छोटे छोटे होटल भी संचालित करते हैं जीमने चाय-मैग्गी आदि की सुविधाएं मिल जाती हैं. 16 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करने बाद 3310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डोडीताल और मां आनपूर्ण के दर्शन होते हैं. खूबसूरत बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बना ये ताल चुटकी में आपकी थकान मिटा देता है. डोडीताल पहुंचने के बाद भी ट्रेकिंग के लिए दरवा टॉप,दवरा पास,चौला दून आदि कई ट्रैक हैं आपको बता दें कि दरवा टॉप से ट्रैकर जानकीचट्टी यमनोत्री भी जाते हैं. ये सारे ट्रैक रूट हरी मखमली घासों से लटे बुग्याल के बीच है.

विश्व प्रसिद्ध है डोडीताल ट्रैक

हर साल देश विदेश से अप्रैल से अक्टूबर तक डोडीताल में ट्रैकिंग के शौकीन पहुंचते हैं. लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक एकैडमी व मसूरी के प्रशिक्षु भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी भी हर साल यहां ट्रैकिंग के लिए पहुंचते हैं.

लण्ढोर

लण्ढोर एक छोटा-सा शहर है जो मसूरी से सिर्फ 7 किमी. की दूरी पर स्थित है। लण्ढोर को मसूरी का ताज भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जगह मसूरी से भी ज्यादा ऊँचाई पर है। लण्ढोर को मसूरी का ही हिस्सा माना जाता है। खास बात ये है कि मसूरी के इतने नजदीक बसे होने के बावजूद ये जगह बेहद शांत और खूबसूरत है। लण्ढोर का नाम असल में ब्रिटेन के एक गाँव के नाम रखा गया है। ब्रिटिश राज के दौरान जब अंग्रेजी सैनिकों को घर की याद आने लगती थी तब वो भारत की ही जगहों का नाम ब्रिटिश शहरों और गाँवों के नाम पर रख दिया करते थे। इसके अलावा ब्रिटिश भारतीय सेना ने यहाँ 1827 में घायल सैनिकों के इलाज के लिए जगह भी बनवाई थी। तब से लेकर अबतक लण्ढोर सेना के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेशन बना हुआ है और इसलिए ये पूरा शहर छावनी क्षेत्र है।

क्या देखें?- वादियों में बसे लण्ढोर में देखने और महसूस करने के लिए असंख्य ऑप्शन्स हैं। अगर आप शहर घूमते-घूमते थक भी गए हैं उसके बाद भी आप केवल अपने कमरे की बालकनी में बैठकर दूर तक फैले पहाड़ों निहारते रह सकते हैं।

केलॉग मेमोरियल चर्च और लण्ढोर लैंग्वेज स्कूल- लण्ढोर में एक रास्ता ऐसा भी है जिसका आकर बिल्कुल 8 की तरह है। इस रास्ते पर एक खूबसूरत और बहुत पुराना चर्च है जिसे आपको देख लेना चाहिए। आम दिनों में इस चर्च के अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है लेकिन बाहर से देखने में ही इस चर्च की भव्यता को आसानी से समझा जा सकता है। चर्च में कांच की खिड़कियाँ हैं जिनको अलग-अलग रंगों से रंगा गया है। चर्च का ढांचा गोथिक आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर बनाया गया है जो इस चर्च को और भी खूबसूरत बना देता है। चर्च के इतिहास के बारे में कहें तो इसका निर्माण 1903 में किया गया था। लण्ढोर लैंग्वेज स्कूल केलॉग मेमोरियल चर्च के ठीक पीछे स्थित है। कहा जाता है भारत में शासन के दौरान अंग्रज़ इसी स्कूल में हिंदी सीखा करते थे। अंग्रेजों की हिंदी भाषा पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए डॉक्टर सैमुएल केलॉग ने हिंदी व्याकरण पर एक किताब भी लिखी थी। खास बात ये है कि इस स्कूल को आज भी चलाया जा रहा है जहाँ दुनियाभर से आने वाले छात्रों को हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू और गढ़वाली जैसी भारतीय भाषाओं की सीख दी जाती है।

सेंट पॉल चर्च- सेंट पॉल चर्च एक छावनी चर्च है जिसका निर्माण 1840 में किया गया था। ये चर्च चार दुकान के ठीक बगल में ही स्थित इसलिए आपको यहाँ पहुँचने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस चर्च की खास बात ये है कि ये पहला ऐसा चर्च है जहाँ राइफल को अंदर लाने की अनुमति दी गई थी। अंग्रेज अफसर अक्सर चर्च के बाहर से राइफल चोरी होने की शिकायत किया करते थे।

लाल टिब्बा व्यू पॉइंट- अगर आपको ट्रेकिंग का शौक है फिर आपने लाल टिब्बा का नाम जरूर सुना होगा। इस जगह को लाल टिब्बा यहाँ पर मिलने वाली मिट्टी की वजह से कहा जाता है जिसका रंग लाल होता है। ये लण्ढोर की सबसे ऊँची जगह है जहाँ से आप कई सारे पहाड़ों को देख सकते हैं। इस व्यू पॉइंट पर दो कैफे भी हैं जहाँ से आप दूरबीन की मदद से इन पहाड़ों को और भी आसानी से देख सकते हैं। ये पॉइंट इतना शानदार है कि आपका मन खुश हो जाएगा। लोकल लोगों का कहना है कि इस व्यू पॉइंट पर आकर आप चार धाम को भी महसूस कर सकते हैं।

फैमिली संग वायनाड घूमने का बना रहे प्लान तो एक्सप्लोर करें ये तीन जगहें, कम खर्च होंगे पैसे

केरल अपनी खूबसूरती के लिए पूरे देश में फेमस है। वहीं केरल में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहे हैं। केरल का पहाड़ी जिला वायनाड अपनी खूबसूरती और शानदार नजारों के लिए जाना जाता है। बता दें कि वायनाड केरल का सबसे शांत और सबसे खास हिल स्टेशन है। ऐसे में अगर आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिल स्टेशनों पर घूम-घूमकर बोर हो गए हैं, तो आपको एक बार वायनाड जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए।

वायनाड में आप ट्रैकिंग, कैंपिंग और सुंदर झरने आदि चीजों को देख सकते हैं। ऐसे में अगर आप भी वायनाड घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है, आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको वायनाड को एक्सप्लोर करने की पूरी जानकारी देने जा रहे हैं।

इस तरह प्लान करें ट्रिप

- अगर आप भी अपने परिवार के साथ वायनाड घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको किसी ऐसी जगह जाना चाहिए, जहां पर आपका कम खर्चा आए। इसके लिए आप ट्रेन के जरिए भी इस ट्रिप को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि फ्लाइट की तुलना में ट्रेन से ट्रैवल करना आपको सस्ता पड़ेगा।
- कम खर्च में ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आप स्लीपर कोच में टिकट बुक कर सकते हैं।
- बता दें कि स्लीपर कोच में 400-500 रुपए का टिकट होगा।
- वहीं अगर आप थर्ड एसी कोच में टिकट बुक कराते हैं, तो आपको एक टिकट के लिए 1100 से 1500 रुपए देने होंगे।

ऐसे बुक करें सस्ते होटल

- अगर आप वायनाड में कम बजट में होटल बुक करना चाहते हैं, तो यह टिप्स आपके बहुत काम आ सकते हैं।
- आप चाहें तो स्टे के लिए पहले से ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हैं।
- अगर आप फैमिली के साथ ट्रिप प्लान कर रहे हैं और कम बजट में रूम चाहते हैं, तो हॉस्टल में भी रहने का प्लान कर सकते हैं।

- हॉस्टल वाले कमरे में 5-6 बेड होते हैं, तो वहीं कई रूम में 3-4 बेड का ऑप्शन होता है। यहां पर आपको 300 से 400 प्रति बेड देने होंगे। इस तरह से आप सस्ते में रूम बुककर पैसे बचा सकते हैं।
- बता दें कि अंबालावायल, पुथेनकुन्न और मानंतवाड़ी में आपको सस्ते होटल मिल जाएंगे।

वायनाड में घूमने की जगहें

- **बाणासुर सागर बांध**- वायनाड जिला अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। वायनाड में बाणासुर सागर बांध एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी बांध है। यहां आपको बेहद सुंदर नजारा देखने को मिलता है, जो आपको यहां पर समय बिताने के लिए मजबूर कर देगा। आप यहां पर बच्चों के साथ बोटिंग कर सकते हैं। पहाड़ी की चोटी से गिरता बाणासुर झरना आपके मन को मोह लेगा।
- **वायनाड वन्यजीव अभयारण्य**- आप बच्चों के साथ वायनाड वन्यजीव अभयारण्य घूमने के लिए जा सकते हैं। यहां पर आप सुबह 7.00 बजे से 10.00 बजे तक और दोपहर 3.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच ही एंट्री मिलती है।
- **एंट्री फीस- बच्चों की एंट्री फीस 5 रुपये हैं।**- यहां घूमने के लिए एक तय समय है, यात्रा समय केवल 1.5 घंटे है।
- बता दें कि यहां पर प्लास्टिक चीजें लेकर जाना मना है।
- **पूकोडे झील**- पूकोडे झील देखने के लिए आप सुबह 9.00 बजे से शाम 5.00 बजे के बीच जा सकते हैं। यहां पर आप बोटिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। अगर आप यहां पर बोटिंग करना चाहते हैं, तो बता दें कि शाम को 4 बजे के बाद बोटिंग के लिए टिकट नहीं मिलता है।
- बोटिंग फीस- अगर आप 2 लोगों के साथ बोटिंग करते है, तो 20 मिनट के लिए 100 रुपये फीस देना होगा।
- फिश स्पा- फिश स्पा के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। इस दौरान सिर्फ आपको 10 मिनट का समय मिलेगा।

युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा डेस्टिनेशन टेंपल वेडिंग का कॉन्सेप्ट, मिलेंगी इतनी सारी सुविधाएं

युवाओं के बीच डेस्टिनेशन टेंपल वेडिंग के बढ़ते कल्चर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के कई मंदिरों को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तैयार करने का फैसला लिया है। क्योंकि आजकल के युवाओं में किसी आध्यात्मिक जगह पर जाकर विवाह करने का ट्रेंड काफी लोकप्रिय हो रहा है। ऐसे में धार्मिक स्थलों पर विवाह से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ऐसे में अगर आप बी किसी आध्यात्मिक जगह पर शादी करना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कई बड़े मंदिरों और वहां पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताने जा रहे हैं।

विवाह के लिए पौराणिक मंदिर

समय के साथ ही युवाओं का टेस्ट डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर बदलता जा रहा है। जहां पहले लोग ऐतिहासिक हवेलियों, भव्य इमारतों, समुद्र के किनारे या पहाड़ों पर शादी करना पसंद करते थे, लेकिन अब युवाओं के बीच डेस्टिनेशन टेंपल वेडिंग का कल्चर काफी पसंद किया जा रहा है। इसके लिए लोग नई-नई जगहों की तलाश कर रहे हैं। वहीं इस रुचि को बढ़ते देख सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने सोमनाथ में विवाह से जुड़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं।

सबसे ज्यादा फेमस मंदिर

महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्यप्रदेश जैसी जगहों से लोग धार्मिक स्थलों पर शादी करने पहुंच रहे हैं। शादी के बाद इन मंदिरों में नए जोड़े से विधि-विधान से पूजा-अर्चना कराई जाती है। ऐतिहासिक और पौराणिक जगहों पर शादी करने में तेजी से लोगों की रुचि बढ़ी है। इस बढ़ते इंट्रेस्ट को देखते हुए ऊखी मठ को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तैयार करने की बात की जा रही थी। क्योंकि यहां पर शादी के लिए अभी से बुकिंग आने लगी है। वहीं तमाम कपल्स त्रियुगीनारायण मंदिर में भी शादी करने में रुचि दिखा रहे हैं। यहां पर सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि कई संतों के आश्रम भी हैं। इसके अलावा ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में भी तमाम परिवार शादी का समारोह आयोजित करते हैं।

बेहद खूबसूरत हैं ये लोकेशन्स

हमारे देश में कई ऐसे धार्मिक स्थल व मंदिर हैं, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। ऊखी मठ और त्रियुगीनारायण मंदिर पहाड़ों के बीच है। तो वहीं सोमनाथ मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। इन जगहों पर डेस्टिनेशन टेंपल वेडिंग की रुचि को तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। वहीं कई मंदिरों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काम कराया जा रहा है।

जो भी सुविधा चाहिए वो लोगों को ट्रस्ट की तरफ से मिल जाती है। शादी के बाद जोड़ा पूजा के लिए सोमनाथ मंदिर में आता है। वहां कोई कार्यक्रम करना है, तो हमने एयरकंडिशन ऑडिटोरियम की सुविधा दी है।% बकौल अजेन्द्र अजय, %हम बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत तमाम मंदिरों में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं।

मंदिरों का पौराणिक- ऐतिहासिक महत्व

ऊखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर के अलावा भी कई मंदिर हैं। इन मंदिरों का अपना ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। हालाँकि यहां पर अभी तक आधारभूत सुविधाओं का ढांचागत विकास नहीं हो पाया था। लेकिन अब ऊखी मठ के पहले फेज का काम शुरू हो चुका है। वहीं त्रियुगीनारायण मंदिर में भी शादी की बुकिंग करवाई जाती है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए लोगों को ज्यादा सुविधाएं देने के लिए डीपीआर तैयार कराया जा रहा है।

मंदिरों में शादी करना है पसंद

वैसे तो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देश-दुनिया में तमाम हसीन और खूबसूरत जगह हैं, लेकिन अब लोगों की दिलचस्पी ऐतिहासिक मंदिर के आसपास वेडिंग शादी करने की बन रही है। जिसका कारण यह माना जा रहा है कि पिछले कुछ समय में देश के कई मंदिर अधिक चर्चाओं में रहे हैं और धार्मिक नगरों का कायाकल्प भी हुआ है। कोरोना महामारी के बाद लोगों का आध्यात्म के प्रति झुकाव हुआ है। वहीं युवाओं में बढ़ी आस्था के कारण लोग आजकल धार्मिक नगरी में शादी करना पसंद कर रहे हैं।

इन मंदिरों में कर सकते हैं शादी

अगर आप भी मंदिर में शादी करना चाहते हैं, तो श्री सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर तरफ से यहां पर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। देश के तमाम लोग सोमनाथ मंदिर में शादी करने आते हैं। वहीं शादी के बाद मंदिर में खास तरह की पूजा करवाई जाती है।

इसके अलावा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तहत आने वाले मंदिरों में डेस्टिनेशन वेडिंग की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए ऊखी मठ में प्लानिंग की जा रही है।

भारत के शीर्ष वेडिंग डेस्टीनेशंस में पुष्कर में स्थित भगवान ब्रह्मा का मंदिर है। इस मंदिर का अपना आध्यात्मिक महत्व है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीओके को लेकर शाह के बयान पर सिब्बल का पलटवार

नईदिल्ली। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अमित शाह के पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया। मौजूदा समय में महंगाई को लेकर पीओके में हिंसक प्रदर्शन जारी है। अमित शाह ने बुधवार को कोलकाता में एक रैली को संबोधित करते हुए पीओके की स्थिति पर बात की। उन्होंने इस रैली में कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और वे इसे ले लेंगे। अमित शाह के इस बयान पर कपिल सिब्बल ने उन्हें घेरा। मीडिया से बात करेत हुए राज्यसभा सांसद ने कहा, वह (अमित शाह) कहते हैं कि अगर हम 400 सीट जीतेंगे तो पीओके वापस ले लेंगे। अगर आप इतनी सीट नहीं जीत पाए तो क्या होगा? आप पीओके वापस नहीं लेंगे? हम चाहते हैं कि आप इसे वापस लें। लेकिन सबसे पहले आपको उस 4000 किमी जमीन को वापस लेना चाहिए, जिसे चीन ने छीन लिया है।

केजरीवाल की रिहाई से भाजपा को नहीं, कांग्रेस को नुकसान

हैदराबाद। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का मानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आकर लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) को नहीं बल्कि कांग्रेस को नुकसान होगा। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (आप) इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस शामिल है। हालाँकि, पंजाब में कांग्रेस और आप एक-दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। दोनों पार्टियां दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, जहां 7 लोकसभा सीटें हैं। तेलंगाना स्थित आरटीवी के साथ एक साक्षात्कार में प्रशांत किशोर ने कहा कि आप पूरे भारत में चुनाव नहीं लड़ रही है। वे 22 सीटों पर लड़ रहे हैं - पंजाब में 14, दिल्ली में 7 सीटें और गुजरात में 1 सीट। अब जो भी बदलाव होना है वह इन 22 सीटों पर ही होगा। इन 22 में से 14 सीटें पंजाब में हैं जहां सीधा मुकाबला आप और कांग्रेस के बीच है। अगर पंजाब में आप को फायदा हुआ तो ये कांग्रेस का नुकसान होगा।

स्वाति मामले में एनसीडब्ल्यू ने विभव कुमार को भेजा समन

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले में बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि मालीवाल निश्चित रूप से विपक्षी दल की नेता हैं, लेकिन बीजेपी यह सुनिश्चित करने के लिए लड़ रही है कि उन्हें न्याय मिले। इधर, एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीएस विभव कुमार को शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर करारा प्रहार करते हुए भाटिया ने कहा कि मामले में केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। मामले पर आखिर वो चुप्प क्यों हैं। यह महिला सम्मान की बात है। यदि आप कुछ नहीं बोल सकते तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश की महिलाएं गुस्से में हैं और अपमानित महसूस कर रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि इसके लिए सिर्फ अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं।

स्वाति विवाद : केजरीवाल और संजय संग दिखे विभव कुमार

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के आरोपों में घिरे निजी सहायक विभव कुमार लखनऊ एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए हमला बोला है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गुरुवार को दावा किया कि तस्वीर से अब सबकुछ स्पष्ट हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने निजी सहायक विभव कुमार को बचा रहे हैं। पूनावाला ने गुरुवार को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से लखनऊ हवाई अड्डे पर आप नेताओं की एक तस्वीर साझा की। इसमें पार्टी प्रमुख केजरीवाल, संजय सिंह और बिभव कुमार साथ में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि 72 घंटे में विभव कुमार पर कोई एफआईआर नहीं हुई, केजरीवाल बचा रहे हैं। बिभव को साथ घूम रहे हैं।

कांग्रेस के बजट पर मोदी की टिप्पणी झूठ : चिदंबरम

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सत्ता में रहने के दौरान पार्टी मुसलमानों के लिए बजट का 15 प्रतिशत आवंटित करना चाहती थी। पीएम मोदी के इस आरोप पर कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस आरोप को गलत बताया। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के बीच हिंदू मुस्लिम विभाजन के मकसद से यह टिप्पणी की है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने पीएम मोदी के इस बयान पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री के बयान लगातार अजीब होते जा रहे हैं और यह दर्शाते हैं कि उनके भाषण लिखने वाले अपना संतुलन खो बैठे हैं। बुधवार को, उन्होंने दावा किया कि अगर उन्होंने हिंदू-मुस्लिम विभाजन किया, तो वह सार्वजनिक जीवन में रहने के योग्य नहीं होंगे। आज, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने का अपना खेल खेला।

तुष्टिकरण के दलदल में धंस चुका है इंडी गठबंधन

प्रधानमंत्री मोदी बोले, सपा-कांग्रेस दो दुकान, झूठ और तुष्टिकरण का सामान बेचते हैं

लखनऊ। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित किया। लालगंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि भारत के लोकतंत्र के महापर्व की खबरें दुनिया के अखबारों में पहले पन्ने पर हैं। ये इसका प्रमाण है भारत की पहचान दुनिया के लिए कितनी अहमियत रखती है, दुनिया देख रही है कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी-एनडीए के साथ है और हमारे सभी मित्रों पर है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है।

नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुधवार को ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो चुका है। ये वो लोग हैं, जो शरणार्थी बनकर लंबे अर्से से हमारे देश में रह रहे हैं, ये वो लोग हैं, जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। इन शरणार्थियों पर वहां तो जुल्म हुआ ही, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबी यहां की सरकारों व उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी।

पीएम मोदी ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं यह मोदी की गारंटी है देश-विदेश कहीं से भी, जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं तुम भी मैदान में हो। लेकिन, आप सीएए को खत्म नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी सीएए लेकर आया है, जिस दिन मोदी जाएगा, ये सीएए भी जाएगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता जान गई है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू-मुसलमान को लड़ाकर सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी सच्चाई बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन मोदी ने आपकी सच्चाई उजागर कर दी है। आपने देश को 7 दशक तक साम्प्रदायिकता की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया था।

उन्होंने कहा कि मोदी ने कश्मीर में शांति की गारंटी दी थी। मोदी ने 370 की दीवार गिराई। पहले चुनाव आते थे तो हड़तालें होती थीं, आतंकी धमकी देते थे, लेकिन इस बार श्रीनगर में पिछले अनेक चुनावों के रिकॉर्ड टूट गए। उन्होंने कहा कि सपा-कांग्रेस, दल दो हैं, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टिकरण का,

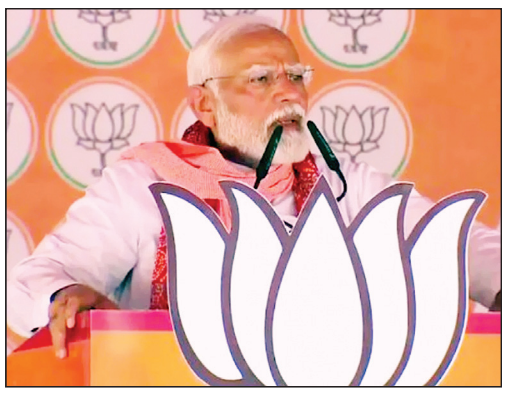

परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन तुष्टिकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है।

पीएम ने कहा कि कांग्रेस महात्मा गांधी का नाम लेकर सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं लेकिन महात्मा गांधी के बातों को याद नहीं रखते, महात्मा गांधी ने ही उन्हें भरोसा दिया था कि वे भारत कभी भी आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार मजबुरन मुसीबत में भारत आए लेकिन कांग्रेस ने कभी इनकी सुध नहीं ली क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं है।

पीएम नरेंद्र नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 साल पहले देश में सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे थी। कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस-किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था। कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे, तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था। लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए ना कुछ सोचती थी ना कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था। स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था इसी रवैया के कारण देशभर में आतंकवाद फला-फूला। अनेक माताओं ने अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा। इन लोगों का आज भी वैसा ही रवैया है। सपा कांग्रेस दल दो हैं, लेकिन दुकान एक ही है। यह झूठ का सामान बेचते हैं। यह तुष्टीकरण, परिवारवार औरऔर भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। आपने समाजवादी पार्टी के गुंडाराज के पुराने दिन देखे हैं, बाज़ार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं-बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी। पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। आज बीजेपी सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है। योगी जी ने दंगाइयों, माफियाओं की, अपहरण, फिरौती गैंग है, मेरा जो स्वच्छता अभियान है योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत मुफ्त व्यवस्था मिलेगी। अब आपके घर का बिजली बिल जीरो हो जाएगा। बिजली इस्तेमाल करने वाला भी हिरो बन जाएगा। सिर्फ निरहुआ ही नहीं आप भी हिरो बन जाइए। अभी से ही इसका रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसमें सोलर लाइट के माध्यम से आप अपने घर की बिजली जलाएंगे। साथ ही ज्यादा बिजली होने पर उसे मुख्यमंत्री योगी खरीद लेंगे। इससे आपकी कमाई भी होगी।

पीएम मोदी ने स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर हमले की कड़ी निंदा की

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को स्लोवाकिया के अपने समकक्ष रॉबर्ट फिको पर गोलीबारी की निंदा की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मोदी ने कहा कि इस घड़ी में भारत स्लोवाकिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। स्लोवाकिया के अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को हैंडलोवा शहर में एक सांस्कृतिक केंद्र के बाहर लोगों का अभिवादन कर रहे प्रधानमंत्री फिको पर कई गोलियां चलाई गईं। फिको (59) इस समय अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ''स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर गोलीबारी की खबर से गहरा सदमा लगा है। मैं इस कायरतापूर्ण और नृशंस कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं और प्रधानमंत्री फिको के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

लखनऊ में अखिलेश और केजरीवाल की संयुक्त प्रेस वार्ता

मोदी की सरकार बनते ही हटाए जाएंगे योगी : केजरीवाल

लखनऊ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखनऊ के सपा कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर मोदी जी चुनाव जीतते हैं तो दो महीने में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटा देंगे। आरक्षण को खत्म कर देंगे। चार जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।

उन्होंने कहा कि मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो रिटायरमेंट की आयु 75 साल रखी गई थी। सुमित्रा महाजन, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी इसका उदाहरण हैं। अगले साल 17 सितंबर को मोदी 75 वर्ष के हो जाएंगे। मोदी ने धीरे-धीरे अमित शाह के रास्ते के कांटो को दूर कर किया। वसुंधरा राजे, सुमित्रा महाजन, शिवराज सिंह चौहान, डॉ. रमन सिंह को हटाया। अब केवल योगी ही बाधा हैं। उन्हें हटाया जाएगा। उन्हें मोदी हटाएंगे क्योंकि अपने बनाए नियम को वो नहीं तोड़ते। वरना लोग उन पर सवाल उठाएंगे। ये नियम उन्होंने आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को हटाने के लिए बनाए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा 220 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, पंजाब और बंगाल में भाजपा की सीटें कम हो रही हैं। केजरीवाल ने कहा कि भाजपा हमेशा ही आरक्षण के खिलाफ रही है। इन लोगों (भाजपा की) की पूरी तैयारी है कि अगर ये जीत गये तो संविधान को बदल कर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा।''

इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि चार चरणों में अब तक भाजपा चित्त हो चुकी है। जनता में आंसुओं का उफान है। 400 पार का नारा इसलिए दिया गया है कि 140 सीटों से ज्यादा नहीं जीत रहे। इस बार जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। उत्तर

प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में भाजपा को करारी हार मिलेगी। रोटी, कपड़ा और मकान के साथ-साथ आरक्षण को बचाना होगा। हारने के बाद ये झूठ का विश्वविधालय खोलेंगे। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मणिपुर के अंदर एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। प्रज्वल रमन्ना ने हजारों महिलाओं के साथ शोषण किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका समर्थन कर रहे हैं। महिला पहलवानों को घर से खींच कर मारा गया। मोदी खामोश रहे। स्वाति मालीवाल जब पहलवान बेटियों के साथ थी तो मारा गया। हालांकि, उन्होंने खुद मालीवाल प्रकरण में गोल मोल जवाब दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया।

केजरीवाल के भाषण पर ईडी ने जताई आपत्ति

नई दिल्ली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत से संबंधित बयानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केजरीवाल के वकील के दावों और जवाबों पर विचार करने से इनकार कर दिया। दरअसल ईडी की ओर से पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुनावी रैलियों में केजरीवाल के भाषणों पर आपत्ति जताई कि अगर लोगों ने आप को वोट दिया, तो उन्हें 2 जून को वापस जेल नहीं जाना पड़ेगा। इस पर पीठ ने मेहता से कहा, यह उनकी धारणा है, हम कुछ नहीं कह सकते।

खेल
प्रमुख समाचार

सुनील छेत्री ने की अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा

नई दिल्ली। भारत के सबसे बेहतरीन फुटबॉलरसुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। 39 वर्षीय छेत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो के माध्यम से घोषणा की, जिसमें उल्लेख किया गया कि 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ भारत का आगामी फीफा विश्व कप क्वालीफायर मैच उनका आखिरी होगा।

छेत्री ने कहा, पिछले 19 वर्षों की स्मृति कर्तव्य, दबाव और अपार खुशी का संयोजन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं देश के लिए इतने सारे खेल खेलूंगा, अच्छे या बुरे लेकिन अब मैंने ऐसा किया लेकिन पिछले डेढ़ दो महीनों में मैंने ऐसा किया। और यह (भावना) बहुत अजीब थी। मैं शायद इस निर्णय की ओर बढ़ रहा था कि यह खेल (कुवैत के खिलाफ) मेरा आखिरी खेल होगा। छेत्री का दो दशकों से अधिक का शानदार करियर है। इस प्रतिभाशाली फॉरवर्ड ने न केवल घरेलू लीगों में अपना दबदबा बनाया है बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपना नाम बनाया है। इसे भाग्य का संयोग ही कहें, छेत्री अपना अंतिम मैच उस शहर में खेलेंगे जहां उन्होंने 19 साल पहले भारत के लिए पदार्पण किया था। विश्व कप क्वालीफायर राउंड 3 में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए कुवैत के खिलाफ भारत का मैच जीतना जरूरी है। वर्तमान में ग्रुप ए में चार मैचों में चार अंकों के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद भारत अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मैच में कतर से भिड़ेगा। केवल शीर्ष दो टीमें ही आगे बढ़ती हैं। सुनील छेत्री ने कहा, एक दिन ऐसा है जिसे मैं कभी नहीं भूलता और अक्सर याद रखता हूं जब मैंने पहली बार अपने देश के लिए खेला था, यह अविश्वसनीय था। छेत्री का सफर 2002 में मोहन बागान से शुरू हुआ। उनकी प्रतिभा ने जल्द ही उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के कैनसस सिटी विजार्ड्स (2010) और पुर्तगाल के स्पोर्टिंग सीपी रिजर्व्स (2012) में कार्यकाल के साथ विदेश में पहुंचा दिया।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 677 अंक उछला निफ्टी 22,400 के पार

नईदिल्ली। एचडीएफसी बैंक और इंफोसिस में खरीदारी के बीच अमेरिकी और एशियाई बाजारों में तेजी के कारण इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी में गुरुवार को लगभग 1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। अत्यधिक उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 676.69 अंक यानी 0.93 फीसदी की बढ़त के साथ 73,663.72 अंक पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 73,749.47 के हाई और 72,529.97 के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 203.30 अंक यानी 0.92 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 22,403.85 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में आज 22,054.55 और 22,432.25 के रेंज में कारोबार हुआ। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, मजबूत वैश्विक रुझानों के कारण घरेलू बाजार में देर से उछाल आया।

अदाणी एनर्जी ने एस्सार ट्रांसको का किया अधिग्रहण

नईदिल्ली। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस ने एस्सार ट्रांसको लिमिटेड (ईटीएल) के 100 प्रतिशत इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण को पूरा कर लिया है। कंपनी ने जानकारी दी कि अधिग्रहण 15 मई को लगभग 11.00 बजे पूरा हुआ। अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के बयान के अनुसार, शेयर अधिग्रहण जून 2022 में हस्ताक्षरित निश्चित समझौतों के तहत हुआ। बयान में कहा गया, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड ने 1,900 करोड़ रुपये के एंटरप्राइज वैल्यू के लिए आवश्यक नियामक तथा अन्य अनुमोदन हासिल करने के बाद एस्सार ट्रांसको लिमिटेड में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल कर ली। इस अधिग्रहण में मध्य प्रदेश में महान को छत्तीसगढ़ में सिपत पूलिंग सबस्टेशन से जोड़ने वाली पूरी तरह से चालू 400 केवी, 673 सर्किट किलोमीटर अंतर-राज्य 'ट्रांसमिशन लाइन' शामिल है।

इंडियन एनर्जी का चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 9.5% बढ़ा

नईदिल्ली। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) का जनवरी-मार्च तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 9.5 प्रतिशत बढ़कर 96.7 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का पिछले साल इसी तिमाही में शुद्ध लाभ 88.34 करोड़ रुपये था। आईईएक्स ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में कुल आय बढ़कर 149.28 करोड़ रुपये हो गई। यह वित्त वर्ष 2022-23 की इसी तिमाही में 129.58 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन अवधि में खर्च 22.65 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले समान अवधि में 19.52 करोड़ रुपये था। समूचे वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी का शुद्ध लाभ 14.7 प्रतिशत बढ़कर 350.78 करोड़ रुपये हो गया। आय बढ़कर 550.84 करोड़ रुपये हो गई। कंपनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.50 रुपये के अंतिम लाभांश की घोषणा की है।

एनर्जी मिशन मशीनरी इंडिया का शेयर बाजार में धांसू एंट्री

नईदिल्ली। एनर्जी मिशन मशीनरी इंडिया के शेयरों ने गुरुवार को एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर शानदार शुरुआत की। कंपनी के इश्यू 366 रुपये पर लिस्ट हुआ। इसका मतलब है कि आईपीओ निवेशकों को 165 फीसदी का लिस्टिंग गेन मिला। आईपीओ लिस्टिंग के कुछ देर बाद ही शेयर में और उछाल देखने को मिला और यह 384.30 रुपये के अपर सर्किट पर पहुंच गए। अब आईपीओ निवेशक 178.48 फीसदी प्रॉफिट में हैं। कंपनी के आईपीओ को ओवरऑल 320 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित हिस्सा 161.92 गुना, नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स का हिस्सा 605.19 गुना और खुदरा निवेशकों का हिस्सा 289.36 गुना भरा था। इश्यू का प्राइस बैंड 131 रु. से 138 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था। एनर्जी मिशन का आईपीओ लॉट साइज 1,000 शेयर था।

वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण में वृद्धि से गरीब वर्ग तक सहायता पहुंचाना हुआ आसान

प्रह्लाद सबनानी

आपको ध्यान होगा कि जब केंद्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर को भारत में लागू करने के प्रयास कर रही थी तब कई विपक्षी दलों ने इस नए कर को देश में लागू करने के प्रति बहुत आशंकाएं व्यक्त की थीं। उस समय कुछ आलोचकों का तो यहां तक कहना था कि वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली देश में निश्चित ही असफल होने जा रही है एवं इससे देश के गरीब वर्ग पर कर के रूप में बहुत अधिक बोझ पड़ने जा रहा है। परंतु, केंद्र सरकार ने देश में पूर्व में लागू जटिल अप्रयत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू कर दिया था तथा इस कर में लगभग 20 प्रकार के करों को सम्मिलित किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू करने के तुरंत उपरांत व्यापारियों को व्यवस्था सम्बन्धी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था। परंतु, इन परेशानियों को केंद्र सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से धीरे धीरे दूर कर लिया गया है एवं आज वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत देश में कर व्यवस्था का तेजी से औपचारीकरण हो रहा है जिससे देश में वस्तु एवं सेवा कर संग्रहण कुलांचे मारता हुआ दिखाई दे रहा है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और यह धन देश की जनता से ही करों के रूप में उगाहे जाने के प्रयास होते हैं। उस कर व्यवस्था को उत्तम कहा जा सकता है जिसके अंतर्गत नागरिकों को कर का आभास बहुत कम हो। जिस प्रकार मक्खी गुलाब के फूल से शहद कुछ इस प्रकार से निकालती है कि फूल को मालूम ही नहीं पड़ता है, ठीक इसी प्रकार की कर व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा, वस्तु एवं कर सेवा के

माध्यम से, देश में लागू करने के प्रयास किये गए हैं। गरीब वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर की दर को या तो शून्य रखा गया है अथवा कर की दर बहुत कम रखी गई है। इसके विपरीत, धनाडय वर्ग द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर की दर बहुत अधिक रखी गई है। वस्तु एवं सेवा कर की दर को शून्य प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत अधिकतम तक रखा गया है।

भारत में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली को लागू किया हुए 6.5 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है एवं आज देश में अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में लगातार हो रही तेज वृद्धि के रूप में इसके सुखद परिणाम स्पष्टत॰ दिखाई देने लगे हैं। दिनांक 1 मई 2024 को अप्रेल 2024 माह में वस्तु एवं सेवा कर के संग्रहण से सम्बंधित जानकारी जारी की गई है। हम सभी के लिए यह हर्ष का विषय है कि माह अप्रेल 2024 के दौरान वस्तु एवं सेवा कर का संग्रहण पिछले सारे रिकार्ड तोड़ते हुए 2.10 लाख करोड़ रुपए के रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो निश्चित ही, भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022 में वस्तु एवं सेवा कर का औसत कुल मासिक संग्रहण 1.20 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो वित्तीय वर्ष 2023 में बढ़कर 1.50 लाख करोड़ रुपए हो गया एवं वित्तीय वर्ष 2024 में 1.70 लाख करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गया। अब तो अप्रेल 2024 में 2.10 लाख करोड़ रुपए के स्तर से भी आगे निकल गया है। इससे यह आभास हो रहा है कि देश के नागरिकों में आर्थिक नियमों के अनुपालन के प्रति रुचि बढ़ी है, देश में अर्थव्यवस्था का तेजी से औपचारीकरण हो रहा है एवं भारत में आर्थिक विकास की दर तेज गति से आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर अब यह कहा जा सकता है कि भारत आगे आने वाले 2/3 वर्षों में 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। भारत में वर्ष 2014 के पूर्व एक ऐसा समय था जब केंद्रीय नेतृत्व में नीतिगत फैसले लेने में भारी हिचकिचाहट रहती थी और भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की हिचकोले खाने वाली 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल थी। परंतु, केवल 10 वर्ष पश्चात केंद्र में मजबूत नेतृत्व एवं मजबूत लोकतंत्र के चलते आज वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है।

छत्तीसगढ़ की धान खरीदी और महतारी वंदन योजना की ओडिशा में मची धूम

भाजपा सरकार बनते ही किसानों से खरीदेंगे 3100 में धान- साय

रायपुर/सुंदरगढ़/बरगढ़/बलांगीर। आज ओडिशा में जनसभा लेने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वहां के भाजपा के संकल्प पत्र पर ख़ुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहाँ भी किसानों को उनके धान की 3100 रूपये की कीमत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज धान खरीदी के मामले में छत्तीसगढ़ उदाहरण बन कर सामने आया है। ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनने पर छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ भी माताओं को महतारी वंदन के जैसे सुभद्रा योजना से आर्थिक मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ से आते हैं। जहाँ अन्नदाता भगवान होता है और धान की बाली महतारी के माथे पर सोने जैसे दमकती है। इसलिए किसान ही छत्तीसगढ़ के सब कुछ हैं, जिसके लिए हमारी भाजपा सरकार समर्पित है। वहां हमारी सरकार वादे के मुताबिक किसानों से इकतीस सौ रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीद रही है, साथ में अंतर की राशि भी एकमुश्त दे रहे हैं। प्रदेश के चौबीस लाख बहत्तर हजार किसानों को इसका लाभ मिला है। ओडिशा में भी भाजपा के घोषणा पत्र में यह वादा शामिल है। जैसे ही 4 जून को यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी तो यहाँ भी इकतीस सौ रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी होगी।

श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत हमारी सरकार सत्तर लाख से ज्यादा माता-बहनों को हर महीने के पहले सप्ताह में ही एक-एक हजार की राशि दे रही है। उसी तर्ज पर ओडिशा में भाजपा सरकार बनते ही सुभद्रा योजना के तहत माता-बहनों को 50 हजार का एकमुश्त वाउचर मिलेगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की गारंटी मतलब गारंटी के पूरा होने की गारंटी। इसलिए ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनाएं, क्योंकि भाजपा जो कहती है उसे करती है। हमारे छत्तीसगढ़ में यही हो रहा है।

सीएम साय ने सुंदरगढ़ के बालीसंकरा, बरगढ़ के बिजेपुर और बलांगीर के बीरमहाराजपुर में भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि यह लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश की बागडोर सौंपने का चुनाव है। मोदी जी गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए गरीबों की पीड़ा उन्हें अच्छे से पता है। नरेंद्र मोदी जी देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबकी चिंता करते हैं। प्रतिदिन 18 घंटे काम करते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने गरीबों को गैस सिलेंडर देने, पक्के घर देने, स्वच्छ पानी, मुफ्त उपचार की सुविधा, बैंक खाता खुलवाने से लेकर शौचालय बनवाने का काम किया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाने, जम्मू एवं कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के साथ देश को आतंकवाद से मुक्ति दिलाने का काम पिछले दस साल में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए देश को फिर से मोदी जी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है। मंच पर विष्णु देव साय ने धान की बालियों की पूजा की और उद्बोधन के दौरान हाथ में बालियों को लेकर घोषणा करते हुए कहा कि ओडिशा में डबल इंजन की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यहाँ भी किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी होगी। यहीं उन्होंने महतारी वंदन योजना के तर्ज पर सुभद्रा योजना लागू करने की भी घोषणा की।

विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल जी ने आदिवासियों के हित के लिए अलग से आदिम जाति कल्याण मंत्रालय बनाया, जहाँ आदिवासी मंत्री पदभार संभालते हैं और बजट की कोई कमी नहीं होती है। आपके ओडिशा के बेटे जुएल ओरांव इस मंत्रालय के दो बार मंत्री बने। इसलिए हम कह सकते हैं कि आदिवासियों का हित भाजपा में ही सम्भव है।

खनिजों के परिवहन के लिए फिर शुरू हुई ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास व्यवस्था

न कोई गड़बड़ न घोटाला, छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला- साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास व्यवस्था की फिर से शुरुआत हुई है. सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर लिखा है कि न कोई गड़बड़ न घोटाला छत्तीसगढ़ सरकार में ईमानदारी का बोलबाला. साय ने आगे लिखा है, हमारा छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा. कोयला सहित अन्य खनिजों के परिवहन के लिए ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास व्यवस्था की पुनः शुरुआत हुई है.

ज्ञात हो कि पिछली सरकार में खनिज विभाग के संचालक द्वारा 15 जुलाई, 2020 को आदेश जारी कर यह व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई-परमिट का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही ई-ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इस आदेश के माध्यम से इसके पहले जो ऑनलाईन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था। जिससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप शुरू हुआ, भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे और परिवहन में भी विलंब होता था।

खनिज विभाग में पूर्व में लागू ऑनलाइन व्यवस्था के तहत कोयले के परिवहन हेतु खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से पट्टेदार द्वारा स्वतः अपने कार्यालय से खनिज परिवहन हेतु ई-परमिट एवं ई-ट्रांजिट पास प्राप्त कर बिना खनिज कार्यालय आये अपना परिवहन किया जा रहा था।

पिछली सरकार में नवीन ऑफलाईन प्रकिया के लागू होने से ई-टीपी लागू करने में विलंब हुआ और कई कोयला खदानों में निकासी अवरूद्ध होने से रायल्टी राजस्व की हानि हुई, जिस पर भारत सरकार ने भी दो बार राज्य सरकार को पत्र जारी कर आपत्ति ली गई थी। इसके अतिरिक्त मानवीय हस्तक्षेप शुरू होने से अवैध उगाही एवं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला एवं प्रदेश की छवि धूमिल हुई।

भ्रष्टाचार के हर आलम का यही आलम होगा : नेताम

नेताम ने झारखंड के गिरीडीह लोस क्षेत्र में संभाली चुनाव प्रचार की कमान

रायपुर। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री तथा झारखंड के पूर्व सहप्रभारी रहे राम विचार नेताम इन दिनों प्रदेश के प्रवास पर हैं। यहां उन्होंने राज्य के गिरीडीह लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार एवं जनसंपर्क अभियान में हिस्सा लिया।

इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर राम विचार नेताम ने कहा कि झारखंड खनिज संसाधनों एवं वन संपदा से संपन्न राज्य होने के बाद भी उसे परिवारवाद ने विकास के मानक में पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा परिवारवाद की वजह से राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। यहां के मंत्री और उनके सहयोगी कमीशन के खेल में व्यस्त हैं। आदिवासी बहुल राज्य में भी आदिवासी समाज विकास की मुख्यधारा से अलग है।

उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं। मंत्री आलमगिरी भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इससे पता चलता है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्रि ने कहा कि जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वह हर भ्रष्टाचारी का यही आलम करेंगी।

उन्होंने कहा, झारखंड से सटे हुए छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन की सरकार आदिवासियों, गरीब, किसान और पिछड़े वर्ग के लिए अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। वहीं झारखंड में उनके हक का पैसा पिता-पुत्र और मंत्री तथा उनके सहयोगियों के कमीशन में खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में झारखंड की जनता प्रदेश की नकारा और भ्रष्ट सरकार का बोरिया बिस्तर हमेशा के लिए बांधने का काम करेगी।

उपमुख्यमंत्री साव ने किया संबलपुर लोकसभा क्षेत्र के सुबनपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित

इस बार फिर जिताकर मोदी का हाथ मजबूत कीजिए- साव

रायपुर। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने गुरुवार (16 मई) को ओडिशा के संबलपुर लोकसभा क्षेत्र के सुबनपुर में %विजय संकल्प रैली% को संबोधित किया। श्री साव ने कहा कि, धर्मेंद्र प्रधान जी ने संबलपुर लोकसभा क्षेत्र का विकास किया है। इस बार फिर उन्हें जिताएं, राष्ट्र निर्माण के लिए पीएम मोदी जी का हाथ मजबूत कीजिए और ओडिशा में भी डबल इंजन की सरकार बनाएं। इससे ओडिशा का चहुंमुखी विकास होगा। साव ने कहा कि, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बुजुर्ग हो गए हैं। उन्हें सेवा की जरूरत है। वो अब क्या लोगों की सेवा करेंगे। अधिकारियों के भरोसे सरकार चला रहे हैं। उन्होंने 24 साल से ओडिशा के विकास को रोके रखा है। प्रदेश को दोनों हाथों से लूटा है। इस बार उन्हें घर बिठाए, और रायलाखोल विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र महापात्रा को भारी मतों से जिताएं।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि, छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी जी गारंटी पूरी हुई है। यहां भी भाजपा की सरकार बनाएंगे तो किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, किसी प्रकार की कटनी छंटनी नहीं होगी। और पैसा 48 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को एक हजार रुपए दे रहे हैं। तीन महीने का पैसा महिलाओं के खाते में भेज दिए हैं। ओडिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, यहां सुभद्रा योजना के तहत 50 हजार रुपए का कार्ड देंगे। जिसे दो साल में खर्च करना होगा। वहीं बुजुर्गों को 3500 रुपए पेंशन देंगे। श्री साव ने कहा कि, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पैसे से वोट खरीदना चाहते है। पैसे और शराब से वोट खरीदना चाहते है, ये किसका पैसा है। ये जनता को फिर लूटना चाहते हैं। लेकिन यहां की जनता बिकाऊ नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने पूछा कि, आपको पांच साल पैसा चाहिए या चुनाव के समय एक दिन पैसा चाहिए। यह आपको तय करना है।

उपमुख्यमंत्री श्री साव ने सुबनपुर की जनता से कहा कि, ओडिशा का विकास चाहिए, किसानों का विकास चाहिए, माता और बहनों का सम्मान चाहिए, तो 25 मई को लोकसभा के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को जिताएं। दिल्ली में वो मंत्री बनेंगे तो आपकी सेवा करेंगे। और विधानसभा में देवेंद्र महापात्रा को जिताएं। ओडिशा में भाजपा की और दिल्ली में मोदी जी की सरकार आपकी जीवन में परिवर्तन लाएगी। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, 24 साल से एक ही सरकार बना रहे हैं। बीजेपी को भी एक मौका देकर देखिए। ओडिशा का विकास करेंगे, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाएंगे। ओडिशा और छत्तीसगढ़ भाई-भाई है। दोनों प्रदेश मिलकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

नवीन ने ओडिशा में कुशासन का कीर्तिमान स्थापित किया

रायपुर। संबलपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा सह प्रभारी एवं रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने कहा कि नवीन पटनायक ने ओडिशा में कुशासन का कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र की योजनाओं पर बाधा अटकाने एवं मोदी सरकार की योजनाओं पर अपने नाम की लीपापोती करने के अलावा कोई काम नहीं किया है। ओडिशा को हर मोर्चे पर आज पिछड़ा हुआ बना दिया है। तमाम खनिज संसाधन, मेहनतकश प्रदेशवासी, केंद्र सरकार द्वारा निरंतर भेजी जा रही भारीभरकम सहायता राशि का भी पटनायक सरकार ने दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा एक पीएम नो सीएम है नवीन बाबू। उन्होंने कहा अब बहुत हुआ इसको शासन का अंत करीब आ गया है जनता बदलाव और परिवर्तन के लिए छटपटा रही है जिस प्रकार केंद्र में मोदी सरकार लोग कल्याण का एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है उसे देख कर जनता भी ओडिसा की कमान भाजपा को सौंपने जा रही है ताकि डबल इंजन की रफ्तार से प्रदेश का विकास हो सके न कि एक पार्टी विशेष और परिवार विशेष का। पुरंदर मिश्रा के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष समेत जिला भाजपा के तमाम पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा के लिए जनता ने मजबूत समर्थन दिखाया।

राइस मिलर्स घोटाला: पूर्व कोषाध्यक्ष को ईडी ने किया गिरफ्तार

रायपुर। ईडी ने छत्तीसगढ़ में राइस मिलर्स घोटाले में एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने कार्यवाही की थी, अब ईडी की एंट्री से कई लोगों की मुसीबत और बढ़ेगी। आरोप है कि एसोसिएशन के पूर्व कोषाध्यक्ष रोशन चंद्राकर ने एमडी मनोज सोनी के साथ मिलकर प्रति क्विंटल 20 रुपये रिश्वत वसूली है। रकम मार्कफेड के जिला अधिकारी को दी गई है। उनके माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया गया। इस दौरान करीब 140 करोड़ रुपए से ज्यादा वसूल किया गया है। जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जिन्होंने रिश्वत दी एमडी ने उनके ही बिल का भुगतान किया। रिश्वत के तौर पर पैसे न देने वालों का भुगतान रोक दिया गया है। कई लोगों के बिल का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। उधर एमडी मनोज सोनी को 28 मई तक जेल भेज दिया गया है। माना तो ये जा रहा है कि मनोज से पूछताछ के बाद ही ईडी ने राइस मिल एसोसिएशन के पदाधिकारी रोशन चंद्राकर को गिरफ्तार किया गया है। ईडी को एमडी मनोज सोनी और रोशन के मोबाइल में मिले चैट, ट्रांजेक्शन के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

मीसा बंदियों के सम्मान निधि भुगतान के लिए 35 करोड़ 42 लाख राशि का आबंटन

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) को लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक एरियर्स एवं चालू वित्तीय वर्ष 2024 में भुगतान हेतु जिला कलेक्टर्स को 35 करोड़ 42 लाख 68 हजार रूपए की राशि का आबंटन सौंपा गया है। इस संबंध में सभी कलेक्टरों को सम्मान निधि भुगतान के संबंध में संशोधित मुख्य शीर्ष-8000 आकस्मिकता निधि से राशि आहरण करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश की अन्य शर्तें यथावत रहेगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि के भुगतान हेतु जिला कलेक्टर्स को जारी आबंटन में से जिला दुर्ग को 8 करोड़ 22 लाख 12 हजार, रायपुर को 6 करोड़ 65 लाख 26 हजार, राजनांदगांव को 73 लाख 78 हजार, बिलासपुर को 3 करोड़ 90 लाख 60 हजार, बस्तर को 35 लाख 65 हजार, सरगुजा को 1 करोड़ 39 लाख 50 हजार, जांजगीर-चांपा को 1 करोड़ 73 लाख 91 हजार, रायगढ़ को 92 लाख 7 हजार, जशपुर को 79 लाख 5 हजार, धमतरी को 2 करोड़ 74 लाख 66 हजार, महासमुंद को 65 लाख 10 हजार, बलौदाबाजार को 55 लाख 80 हजार, बेमेतरा को 27 लाख 90 हजार, बालोद को 44 लाख 2 हजार और मुंगेली जिले को 65 लाख 72 हजार रूपए की राशि आबंटित की गई है।

झारखंड में चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे कौशिक

रायपुर। लोकसभा 2024 चुनाव के अंतर्गत झारखंड के जमशेदपुर में भाजपा प्रत्याशी विद्युतवरण महतो के पक्ष में घाटशीला विधानसभा स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा से वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष बड़कुंवर गागराई, प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू एवं घाटशीला विधानसभा के समस्त ऊर्जावान कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के कई सांसद एवं विधायक तथा पदाधिकारी इन दिनों झारखंड के प्रवास पर हैं। यहां वह अलग-अलग लोकसभा क्षेत्र में चुनावी जनसंपर्क में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

हज्जे बैतुल्लाह जाने वाले जायरीनों का हुआ टीकाकरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी की सदस्य डॉक्टर श्रीमती रूबीना अल्वी ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के तत्वाधान मे होटल एबीस ग्रीन राजनांदगांव में सन् 2024 में राज्य से द्वितीय चरण में मुंबई एवं नागपुर एम्बार्केशन पॉइंट से जाने वाले आज़मीने हज का टीकाकरण कराया गया। जिसमे हज यात्रियों को स्वास्थ्य सम्बंधित सावधानियों से भी अवगत कराया गया। शिविर में राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़ छुईखदान, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद के कुल 235 हज यात्रियों का टीकाकरण संपन्न हुआ। शिविर में मुख्य रूप से मोहम्मद असलम खान, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, डॉ. श्रीमती रूबीना अल्वी, सदस्य, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी, शाहिद भाई, अंजुम अल्वी, हाजी रज्जाक बडगुजर,उपस्थित रहे। हज यात्रियों के टीकाकरण का कार्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री डा एन आर नवरत्न एवं जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ बी एल तुलसी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा दल द्वारा किया गया।

ओडिशा में बृजमोहन के रोड शो में उमड़ी भीड़, जनता में जबरदस्त उत्साह

कांटाबांजी के ग्रामीण इलाकों में घर-घर जाकर मांगे वोट

रायपुर/कांटाबांजी। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल इन दिनों ओडिशा में चुनाव की कमान संभाले हुए हैं। इसी क्रम में गुरुवार को उन्होंने कांटाबांजी के ग्रामीण इलाकों में जनसंपर्क कर भाजपा के लिए वोट मांगे। बृजमोहन अग्रवाल ने तुरेकला, बड़बांकी, गुनेश समेत कई इलाकों में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया और घर-घर जाकर भाजपा की नीति और रिति का प्रचार किया। बृजमोहन अग्रवाल को अपने बीच में पाकर ग्रामीणों में खासा उत्साह देखा गया। जगह-जगह ग्रामीणों ने बृजमोहन अग्रवाल का पारंपरिक तरीके से आरती उतार कर और माला पहनाकर स्वागत किया।

इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने भी लोगों का मान रखते हुए उन्हें संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नवीन पटनायक सरकार ने 25 सालों से पश्चिम ओडिशा की अनदेखी की है। जिसका नतीजा है की इलाके में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है साथ ही बेरोजगारी भी यहां की एक बड़ी समस्या है। रोजगार के तलाश में लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। पैसों के अभाव में छोटी-मोटी बीमारी होने पर भी गरीबों को

इलाज करने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब समस्याओं से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है राज्य में लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा में भी भाजपा को बहुमत के साथ लाना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं सभी का ख्याल रखते हुए भारत को विकसित देश बनाने का कार्य कर रहे हैं और जिन राज्यों में भाजपा सरकार है वहां भी विकास तेज गति से हो रहा है। राज्य में भाजपा सरकार आने पर गरीबों के लिए पक्का मकान, गैस कनेक्शन, हर घर नल से जल, महिलाओं को ?1000 प्रतिमाह, किसानों को सम्मान निधि और धान का उचित मूल युवाओं को स्व रोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना भाजपा सरकार की प्राथमिकता होगी। छत्तीसगढ़ में जब से भाजपा सरकार बनी है तब से ही यह सभी लाभ वहां की जनता को मिलाने लगे हैं।

प्रदेश में 13 जून को दस्तक देगा मानसून

रायपुर। देश के मानसून की 31 मई से हो सकती है. केरल में मानसून के दस्तक देते ही अन्य राज्यों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी. वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है. इस बार छत्तीसगढ़ में मानसून की एंट्री 13 जून को हो जाएगी. इस बार पिछले से अच्छी बारिश होने की भी उम्मीद है. यह मानसून किसानों के लिए काफी बेहतर हो सकता है. 106 फीसदी तक बारिश होने का पूर्वानुमान है.

मानसून को लेकर मौसम वैज्ञानिक एचपी चंद्रा ने बताया कि मानसून के जगदलपुर पहुंचने की सामान्य तिथि 13 जून है. रायपुर में 16 जून है और अंबिकापुर में 21 जून है. इस साल वर्षा 106 प्रतिशत होने की उम्मीद है. इसका मतलब है कि सामान्य से इस वर्ष अधिक बारिश होने की संभावना है. इस मुख्या कारण एल नीनो है वह इफ़ेक्ट करता है. एल नीनो प्रभाव कम हो गया है यानी न्यूट्रल कंडीशन पर है. जिसके कारण इस साल अच्छे मानसून की संभावना है. अच्छी बारिश से किसानों को फसल उत्पादन में काफी मदद मिलेगी.

बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून को लेकर अपडेट दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण-पश्चिमी मानसून की शुरुआत केरल में 31 मई के आसपास होने के आसार हैं. दक्षिण-पश्चिम मानसून आम तौर 1 जून को केरल में प्रवेश करता है. इसके बाद यह आमतौर पर उत्तर की ओर बढ़ता है और 15 जुलाई के आसपास पूरे देश को कवर कर लेता है. आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया है कि यह जल्दी नहीं है. यह सामान्य तारीख के करीब है क्योंकि केरल में मानसून की शुरुआत की सामान्य तारीख एक जून है.

आईएमडी ने 2024 में औसत से अधिक मानसूनी बारिश का अनुमान लगाया है.

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.